हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

LIBRARY

विषय सूची

मंगलवार, 18 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	31
अनुपस्थिति की अनुमति	34
बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट में संशोधन	34
वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	35

मूल्य : 45

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ. रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now questions hour.

Construction of Roads in Bhiwani

*** 874. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Bhiwani :—

(i) Village Nangal to Ajitpur ;

(ii) Village Dhana Narsan to Bhiwani ;

(iii) Village Jharvai to Lohari ;

(iv) Village Haluwas to Mukti Dham Haluwas Gate Bhiwani ;

(v) Village Dhana Narsan to Ajitpur ;

(vi) Village Roop Garh to Dhani Janga (Luharerei) ;

(vii) Village Roop Garh to Dhirana ; and

(viii) Village Haluwas to Dhana Ladanpur ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, out of eight roads, one road mentioned at Sr. No. (iii) from Village Jharvai to Lohari already stands constructed. There is no proposal at present with the department to construct the remaining roads.

Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Mr. Speaker Sir, the number of roads which have already been enlisted, are very essential. I would request the Hon'ble Minister that if not all roads, few roads must be completed by the PWD (B&R) and rest may be completed by the Marketing Board. स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने सवाल में आठ सड़कों का जिक्र किया है, उनमें से गांव धाना नारसन से भिवानी की सड़क विलेज हालूवास टू भुक्सि धाम हालूवास गेट टू भिवानी, विलेज ढाणा नारसन टू अजीत पुर, विलेज रूपगढ़ से ढाणी जंगा तक दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है कि यह सड़क 33 फुट का कन्सोलिडेशन पाथ है। विलेज ढाणा नारसन से हालूवास तक तो आधे पोर्शन में 33 फुट का पाथ है लेकिन बाकी के ऐरिया में पाथ नहीं है। इनकी जो दो सड़कें हैं विलेज नांगल टू अजीत पुर, झारवई से लोहारी और रूपगढ़ से ढाणी जंगा है इसमें केवल 22 फुट का रास्ता है और सरकार की नीति के मुताबिक 22 फुट का जहां रास्ता है वहां पर लैंड ऐक्विजीशन में काफी पैसा लगता है। स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में अभी विचार नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान में कुल 250 किलोमीटर सड़कें बनी थीं और मौजूदा सरकार ने 328 किलोमीटर सड़कें अपने तीन साल के कार्यकाल में बना दी हैं। मैं माननीय इन्दौरा साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में कुल 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था जबकि हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल के दौरान 328 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 421 किलोमीटर सड़कों का काम अण्डर प्रोग्रैस है यानि सात सौ किलोमीटर से अधिक सड़कें बना दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की मन्शा रहती है कि हरेक क्षेत्र में प्रदेश का बराबर विकास हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई सड़कें ऐसी बताई हैं जो बननी बहुत जरूरी हैं। मैं इसके बारे में माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे एक जरूरी सड़क का नाम बता दें सरकार उसको बनाने बारे विचार कर सकती है।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि एक सड़क तो काफी कम है इसलिए कम से कम दो सड़कें तो जरूर बनवा दें। रूपगढ़ से ढाणी जंगा की अपनी पंचायत नहीं है और रूपगढ़ के साथ उनकी ग्राम पंचायत है। मेरा कहना तो यह है कि रूपगढ़ टू ढाणी जंगा की रोड अगर बनवा देंगे तो उससे वहां के ग्रामवासियों को काफी फायदा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि नांगल टू अजीत पुर विलेज की जहां तक बात है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला नांगल गांव में गए थे वहां पर मेरी कांस्टीच्यूएंसी में उनका प्रोग्राम था। वे मेरे हल्के के कई गांवों में गए थे और उन्होंने वहां पर अनाऊंसमैंट भी की थी कि गांव नांगल से अजीतपुर तक सड़क हम बनवा देंगे। इसमें कच्चा रास्ता पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इन दोनों सड़कों के लिए तो आपसे प्रार्थना है कि पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्ड आर०) से बनवाने की कृपा करें और बाकी की जो सड़कें हैं क्या उनको मार्कीटिंग बोर्ड से बनवाने की कृपा करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां तक नांगल से अजीतपुर रोड का सवाल है, यह सड़क तकरीबन 3.20 किलोमीटर लम्बी सड़क है और इस पर 22 फुट का कंसोलिडेशन पाथ अवेलेबल है। उस रोड के लिए लैण्ड ऐक्वीजीशन पर 93 लाख रुपए लगेंगे और 179 लाख रुपए उसकी कंस्ट्रक्शन पर लगेंगे। यह रोड फीजिबल नहीं है क्योंकि इस सड़क को बनाने में काफी पैसा खर्च होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है

कि हरेक क्षेत्र का बराबर का विकास हो, इस बात को देखते हुए जो उन्होंने रूपगढ़ से ढाणी जंगा रोड की बात कही है, उसको जरूर सरकार बनवा देगी। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार की मंशा है कि सड़कों की मैनटेनैंस और रिपेयर अच्छी तरह से की जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में मैनटेनैंस और रिपेयर पर 1744 करोड़ रुपए खर्च किए थे और हमारी सरकार ने इन 3 साल के कार्यकाल में मैनटेनैंस, रिपेयर और न्यू कंस्ट्रक्शन पर 2100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों पर पिछली सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए से कम खर्च किए थे और मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसमें 2007-08 में 360 करोड़ रुपए की मंजूरी मौजूदा सरकार को मिली है। अध्यक्ष महोदय, एन०सी०आर० में पिछली सरकार ने अपने 5 सालों में सड़कों पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इसके मुकाबले हमने 2007-08 में 1200 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए हैं। नाबार्ड के इन्होंने मात्र 5 सालों में सड़कों पर 30 करोड़ रुपए ही खर्च किये थे और हमने अपने इन 3 सालों में सड़कों पर 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, अब चाहे बिल्डिंग्ज हों, ब्रिजिज़ हों या दूसरी चीजें हों यह सरकार उनको बनवा रही है।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की मंशा है कि जो भी अनाऊंसमैंट करते हैं या नींव पत्थर रखते हैं उसको ये जरूर पूरा करेंगे। यह जो नांगल टू अजीतपुर सड़क है उस बारे में माननीय मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जब वहां पर गए थे तो उस बारे में अनाऊंस कर के आए थे कि वे इस सड़क को बनवाएंगें। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को ये जरूर बनवाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, बात यह है कि कई बार मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को अनाऊंसमैंट करनी पड़ जाती है लेकिन जब बाद में डिपार्टमैंट उस बारे में एग्जामिन करवाते हैं तो उसमें कई दिक्कतें सामने आती हैं जब उस बारे में मुख्यमंत्री जी को बताया जाता है तो मुख्यमंत्री जी भी कह देते हैं कि इसको छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर साहब जिस सड़क के बारे में कह रहे हैं यह सड़क 3.5 किलोमीटर लम्बी है और उसको बनाने पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए कास्ट आएगी। वहां पर लैंड इक्वीजीशन की दिक्कत आ रही है और वहां पर मिट्टी भी बहुत दूर से लानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, उसमें कास्ट फैक्टर बहुत ही ज्यादा है। आप वहां पर लैंड दिलवा दें तो हम उसको बनवा देंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, मंत्री जी बहुत ही काबिलियत से जवाब दे रहे हैं। इन्होंने शिव शंकर भारद्वाज जी को बताया कि अनाऊंसमैंट प्रोग्रामों को भी कई बार कैंसिल करना पड़ता है। मंत्री जी, हमारी सरकार ने कई-कई गांवों को एक-एक या दो-दो सड़कें दे दी हैं। लेकिन मंत्री जी को याद होगा कि कई लोग ढाणियों में बसे हुए हैं। उन ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का काम कब तक यह सरकार पूरा कर देगी ताकि वहां के लोगों को भी कुछ राहत मिल सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सभी ढाणियों को सड़कों से जोड़ा जाए यह पोसिबल नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुलाना जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री जी से ये अपने काम करवा लेते हैं और मेरे दोस्त भी हैं। हमने इनके यहां पर कई सड़कें मंजूर की हैं और इसके बावजूद भी इनकी कोई सड़क रिपेयर करवाने की है या बनवाने की है तो हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री फूलचन्द मुलाना : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी सीट का माईक खराब होने की वजह से दूसरी आगे वाली सीट पर से बोलने की परमिशन दी। अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी सवाल के जवाब में बड़े दबंग दावे कर रहे थे और रिप्लाई देते हुए कह रहे थे कि हमने इतनी लम्बी सड़कें बना दी, इतने करोड़ों रुपए खर्च किए और समान रूप से विकास किया। अध्यक्ष जी, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर हैं ये मेरे साथ चलें और हमारे यहां पर जो महत्व की सड़कें हैं उनको देखना चाहें तो देखें कि उनकी हालत क्या है। अध्यक्ष जी, सिरसा से ऐलनाबाद की जो सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है। ये बताएं कि उसको ये क्यों नहीं ठीक करवा पाए? इसी तरह से कुरला से जाखल की जो सड़क है उसकी भी हालत बहुत खराब है मंत्री जी, क्यों नहीं इस सड़क को ठीक करवा पाए?

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी इन सड़कों को प्राथमिकता के तौर पर मजबूत बनाने और रिपेयर करवाने की कृपा करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि जब चौटाला साहब की सरकार थी तो उस दौरान इन्होंने 6 साल तक इस प्रदेश पर राज किया लेकिन उस समय सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। जैसा मैंने बताया कि इन्होंने अपनी सरकार के दौरान पांच साल में केवल 1744 करोड़ रुपए सड़कों की रिपेयर के ऊपर खर्च किए। उस समय ये सारी सड़कें टूटी हुई सौंपकर गए थे। मौजूदा सरकार आने के बाद हमने 2100 करोड़ रुपए इन तीन सालों में सड़कों की मेंटीनैंस और नयी सड़कों की कंस्ट्रक्शन में लगाए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 700 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। इसमें हमने सड़कों को 12 फुट से 18 फुट चौड़ा किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 में हमने 360 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन करवाए हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे एन०सी०आर० में हो या चाहे नाबार्ड में हो अगर आप इनके समय के मुकाबले हमारे आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि हमने सड़कों पर बहुत कार्य करवाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो सड़कों के बारे में जिक्र किया है। सिरसा से ऐलनाबाद और कुरला से जाखल तक की सड़क के बारे में इन्होंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, ये मुझे यह बताएं कि क्या आज तक इन्होंने कभी इस बारे में मुझे लिखकर दिया है कि फलाना सड़क मेरे हल्के की खराब है उसको ठीक करवा दीजिए। ये बताएं कि क्या कभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस बारे में लिखकर दिया है कि हमारे हल्के की ये नयी सड़कें बनायी जाएं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल अपनी बात दर्ज कराने के लिए यहां पर इस तरह

की बात करते हैं ताकि इनकी बात अखबारों की हैड लाईन में आ जाए। ये कभी भी इस बारे में मुझसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले और न ही कभी इनकी इस बारे में चिट्ठी आयी है इन्होंने आज ही यह मामला उठाया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, आप देखें कि मैं आलरेडी पहले सैशन में ही इनको इस बारे में लिखित तौर पर दे चुका हूं। जब मैं यहां पर कह रहा हूं तो लिखकर देने की वैसे भी कोई बात नहीं है। अगर हम यहां पर अपनी बात नहीं कह सकते तो फिर सैशन किस लिए होता है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक विधायक का फर्ज यह बनता है कि वह अपने हल्के की देखभाल करें। लेकिन इनके नेता तो दो-दो साल तक विदेश में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इनकी हल्के की जिम्मेवारी नहीं है इनकी तो हरियाणा की जिम्मेवारी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यही बात मैं भी कह रहा हूं। वे विपक्ष के नेता तो बन नहीं पाए इसलिए वे दो साल तक विदेश में ही घूमते रहते हैं। इन्होंने जिन दो सड़कों का जिक्र किया है उनके बारे में मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि हम इनको ऐग्जामिन करवा लेंगे और अगर वे रिपेयर करने लायक हुई तो जरूर उनको रिपेयर करवा देंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इनकी सड़कों को ठीक करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बाकी सब बातें तो ठीक हैं लेकिन इन्दौरा साहब बताएं कि जब अभी इनका माईक खराब हो गया था तो ये बोलने के लिए आगे चौटाला साहब वाली सीट पर क्यों नहीं आए, क्या यह उनको करन्ट मारती है? ये दूसरी सीट पर तो आगे आकर बोले लेकिन ये चौटाला साहब वाली सीट पर क्यों नहीं आए? अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि ये आगे की सीट पर आ जाएं।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डॉ० शिव शंकर भारद्वाज जी ने जो क्वैश्चन रखा है उसके बारे में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि करीब 15-20 साल पहले पंचायती राज संस्था की तरफ से मेरे हल्के में कुछ सड़कें बनाई गई थीं, अब उन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। मेरे हल्के में बवानी खेड़ा से खेड़ी जालब और अलखपुरा तक सड़क बना दी अब उस सड़क को न तो पंचायती राज डिपार्टमैंट बनाता है न मार्किटिंग बोर्ड बनाता है और न ही पी०डब्ल्यू०डी० डिपार्टमैंट इनको बना रहा है। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बोहर से खानक तक किरावड़ से कुंगड़ होते हुए गढ़ी तक नयी सड़क बनाने का कोई प्रावधान मंत्री जी ने रखा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कुछ सड़कें पंचायती राज संस्था के द्वारा पहले बनाई गई थीं लेकिन अब वे रिपेयर नहीं हो रही हैं। इस बारे में इनका पहले भी सवाल आया था। मैं इनको बताना

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
चाहूंगा कि 110 सड़कें ऐसी हैं जो कि पंचायती राज द्वारा बनाई गई थीं जिनको अब हमने टेकओवर कर लिया है जिनमें से 51 सड़कें रिपेयर कर दी हैं। जिस सड़क का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसको भी हम रिपेयर कराएंगे, यह मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन देता हूं। जिन नयी सड़कों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है पहले हम उनकी फिजीबिलिटी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि उनमें कंसोलिडेशन वर्क कितने हैं, कितना उसमें पैसा लगेगा तभी मैं उन सड़कों के बारे में हाउस में आश्वासन दे सकूंगा या फिर माननीय सदस्य इस बारे में अलग से नोटिस दे दें तो इसको मैं अलग से ऐग्जामिन करवा कर फिर इस बारे में आश्वासन दे सकूंगा।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मानेसर से तावडू की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है और नौरंगपुर, मौहम्मदपुर अहीर और तावडू तक जो सड़क जाती है वह काफी मेन सड़क है और यह सड़क गुड़गांव से जोड़ती है। ये सारे गांव मेन सड़क पर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हैं और इनमें 2-3 ढाणी भी हैं। क्या मंत्री जी उन सड़कों के बारे में कुछ करने जा रहे हैं ताकि ये सड़कें बन जाएं और मेवात इलाके की हालत भी थोड़ी बहुत सुधर जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप यह बताएं कि नयी सड़कें बननी हैं या रिपेयर होनी हैं?

श्री साहिदा खान : नयी भी बननी हैं और रिपेयर भी होनी हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या वह एक ही सड़क है जो नयी भी बननी है और रिपेयर भी होनी है।

श्री साहिदा खान : सर, एक सड़क का एक टुकड़ा है जो नया बनना है बाकी की सड़क की रिपेयर होनी है। मैं ज्यादा नाम बताता हूं तो आप नाराज होते हैं इसलिये इकट्ठे ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नाराज कोई नहीं होता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मानेसर से तावडू वाली सड़क का जिक्र किया है, उसके बारे में मैंने कल भी क्वैश्चन ऑवर के दौरान माननीय सदस्य को बताया था कि 588 करोड़ रुपया मेवात के लिए एन०सी०आर० में हमने मंजूर करवाया है। मानेसर से तावडू जो सड़क है उस पर राजस्थान से बहुत सारे डम्पर आते हैं। उस सड़क का आधा पोर्शन तो ठीक है और जो बाकी का आधा है उसको हम एन०सी०आर० या नाबार्ड की स्कीम के तहत रिपेयर कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब चौटाला साहब की सरकार थी तब बिल्डिंग्स को बनाने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम जरूर किया गया था। जो इनका विरोधी होता था उसकी बिल्डिंग ये तोड़ देते थे। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने बने बनाए मकान तोड़े थे। बिल्डिंग्स पर इनकी

सरकार ने साढ़े पांच साल के समय में 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे और मौजूदा सरकार ने तकरीबन एक हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिये हैं और करीबन 425 करोड़ रुपये और खर्च करने हैं। इसके अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपए के काम इस समय चल रहे हैं। इस विधान सभा भवन का काम भी पी०डब्ल्यू०डी० बी० एण्ड आर० ने किया है इसके लिए मैं विशेष तौर पर सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा सभी सदस्यों ने विधान सभा के भवन के काम के लिए धन्यवाद किया है लेकिन विपक्ष के साथियों ने तो इस बारे में धन्यवाद भी नहीं किया है।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : हमने पहले ही धन्यवाद किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यह तो अच्छी बात है कि आप कहीं बधाई तो देते हैं। बहुत मेहनत से हमारे बी० एण्ड आर० के अधिकारियों ने काम किया है।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, हमने धन्यवाद किया है। जबकि कैप्टन साहब कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद नहीं किया। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं हमने इस रेनोवेशन के बारे में धन्यवाद किया है यह रिकॉर्ड की बात है। धन्यवाद तो हमने किया है।

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी, आपने किया है, इन्दौरा जी ने धन्यवाद किया। आपकी पार्टी के लीडर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तजुर्बेकार मैम्बर हैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए था कि कितना जबरदस्त तरीके से रेनोवेशन किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे बी० एण्ड आर० के आफिसर्ज ने यह रेनोवेशन का काम किया है। दूसरी बात मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हरियाणा भवन का रेनोवेशन भी चल रहा है जो काफी जर्जर हालात में हो गया था। इसके अलावा प्रदेश में 70-80 प्रतिशत रैस्ट हाउसिज को इस सरकार के आने के बाद रिपेयर करवाया है और ठीक भी करवाया है। मौजूदा सरकार आने के बाद चाहे सड़कें हों, चाहे बिल्डिंग्ज की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री रोज़गार सड़क योजना की बात हो हमने सभी को रिपेयर करवाया है।

श्री अध्यक्ष : पिछली सरकार के समय कितने रैस्ट हाउसिज को बेचा गया और कितने रैस्ट हाउसिज नीलाम हो गये थे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कई रैस्ट हाउसिज को बेचने का काम कर दिया था लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाया और कम से कम 20-22 ऐसे रैस्ट हाउसिज जो बहुत ही पुराने रैस्ट हाउसिज थे उन रैस्ट हाउसिज को बचाया है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय,*** *** ***

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय,*** *** ***

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि आदरणीय इन्दौरा जी तजुर्बेकार सदस्य हैं और ये संसद में भी सदस्य रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में यहां पर कोई टीका-टिप्पणी करना संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। फिर भी इन्होंने यह विषय उठाया है। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार ने पूरे मामले की तहकीकात की है। डॉ० राम प्रकाश जी ने और उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी यह दरख्वास्त नहीं दी कि हमें जमीन का एक्सचेंज करना है। डॉ० राम प्रकाश जी को ग्राम पंचायत का ऑफर गया था। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए कि उनकी जमीन से ग्राम पंचायत जमीन एक्सचेंज करना चाहती है क्योंकि ग्राम पंचायत की जो जमीन थी वह छः फीट गहरी थी उस जमीन के अन्दर उस इलाके का सारा पानी इकट्ठा हो जाता था। उस जमीन पर 13 बिजली के खम्बे लगे हुए थे जिसकी वजह से उस जमीन को 5-7 हजार से ज्यादा कोई ठेके पर भी नहीं लेता था। ग्राम पंचायत ने डॉ० राम प्रकाश जी की धर्म पत्नी को यह प्रस्ताव दिया और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि यह जमीन उनकी जमीन के साथ लगती थी इसलिए उस जमीन को एक्सचेंज कर लिया। यह भी गलत रिपोर्ट है कि यह सब कार्यवाही एक दिन में हो गई। इस प्रक्रिया के अन्दर एक महीना लगा। इसके लिए बाकायदा ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया, ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास किया उसके बाद इन्होंने इस बात को स्वीकार किया उसके बाद इस जमीन का हस्तांतरण हुआ। फिर भी ये इस बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो मेरे पास आ जायें मैं इनको यह सब प्रक्रिया दिखा दूंगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रैस्ट हाउसिज की बात आई है तो मैं कल आपको सारे आंकड़े दे दूंगा कि इन्होंने कितने रैस्ट हाउसिज बी०एण्ड आर० के और कितने रैस्ट हाउसिज इरीगेशन डिपार्टमैंट के बेचने का काम कर रखा था जिन पर हमने आकर रोक लगाई थी इस बारे में मैं सारे फैक्टस कल हाउस में दे दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने घोटाले कर रखे थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एण्ड डिवैल्पमैंट के चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय यहां मौजूद हैं, बी० एण्ड आर० के हमारे आदरणीय मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं और ये इरीगेशन के मिनिस्टर भी हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे और माननीय मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि कम से कम सदन के पटल पर एक जानकारी अवश्य रख दें कि कितनी जमीनें पिछली सरकार के कार्यकाल में बेच दी गई और कितनी जमीनें देवीलाल ट्रस्ट को बगैर पैसा लिए तोहफे के तौर पर दे दी गई। यह जानकारी इनको सदन में रखनी चाहिए ताकि सदन को पता चले कि सरकार की बेशकीमती करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किसने किया and by way of a special mention ये इस चीज को हाउस में लेकर आएं ताकि हरियाणा की जनता को फैक्चुअल जानकारी पता चले कि इन्होंने क्या-क्या किया। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, जींद शहर में एक धार्मिक जयन्ती देवी मन्दिर है जो गवर्नमैंट के अंडर है। जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी उस मन्दिर के पास 4 एकड़ जमीन शहर के बहुत अच्छे एरिया में थी और बहुत कीमती जमीन थी, इनकी सरकार ने अपने आदमी द्वारा एक घटिया जमीन जिसमें 20 फुट गड्ढे थे उसको

परचेज करवाकर उस बढ़िया जमीन से ट्रांसफर करवा दी, इसका शहर में बड़ा भारी प्रोटैस्ट हुआ था और रिसैंटमैंट हुआ था, इन्होंने तो देवी की भी परवाह नहीं की, भगवान की भी परवाह नहीं की और उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके शापिंग काम्पलैक्स बनवा कर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा अन्याय इनकी सरकार के समय में हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस० एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले नम्बर पर तारांकित प्रश्न संख्या 838 लगा हुआ था इस बारे में मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि जब मैं सदन की बैठक अटैंड करने के लिए आ रहा था तो उस समय वी०वी०आई०पी० कारकेड गुजर रहा था और जिसके कारण रास्ते में अवरोध लगा हुआ था। इसलिए मुझे वहां पर रुकना पड़ा और मैं लेट हो गया और इसी कारण मेरा सवाल भी लग नहीं पाया। मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि मुझे अब अपना सवाल पूछने की परमिशन दी जाए।

Mr. Speaker : Surjewala ji, your request is acceded to. You may ask your question.

Average Rainfall in Haryana

***838. Sh. S. S. Surjewala :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) the average rainfall in various parts of Haryana together with the status of the rainfall both Monsoon and Winter rains during the last five years separately ;

(b) whether it is a fact that the Monsoon has changed its course during the last 4-5 years ; and

(c) if so, the measure adopted by the Government to help the farmers on this account ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : (a) to (c) Sir, the information is laid on the Table of the house.

Information

(a) The District wise average rainfall both Monsoon and Winter rains during last five years in Haryana is annexed at "A"

(b) Yes, there appears to be significant variation in the pattern of the monsoons during the last five years.

(c) Despite deficient rains the state has been able to achieve the highest foodgrain production during 2006-07 i.e. 147.63 lac M.Ts. The Department of Agriculture has undertaken measures for dissemination

[Sardar H.S. Chatha]

of better crop management practices and the State Government has ensured adequate power to the farmers for tubewells so that they are able to irrigate their fields in deficient rainfall areas. The Irrigation Department has also taken special steps to ensure adequate availability of canal water for irrigation.

Annexure-A

Year-wise Monsoon and Winter rain for the year 2003 to 2007

(Fig. in mm.)

Year	Monsoon Rains			Winter Rains		
	Actual	Normal	%age Dep.	Actual	Normal	%age Dep.
1	2	3	4	5	6	7
2003-04	608.2	532.5	14	52.2	84.3	–38
2004-05	458.8	535.0	–14	152.8	83.6	82
2005-06	523.2	532.3	–2	43.8	83.3	–47
2006-07	326.8	532.7	–39	141.5	83.3	70
2007-08	287.5	532.7	–46	4.7	68.0	–93

District Wise/Year-wise Monsoon and Winter rain for the year 2003 to 2005

Year 2003

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	892.9	818.9	9	90.7	145.2	–37
Bhiwani	381.5	372.2	3	21.4	55.3	–62
Faridabad	936.3	474.9	97	53.5	52.8	2
Fatehabad	395.4	317.3	25	25	58.5	–58
Gurgaon	735	526.9	39	37	59.6	–38
Mewat	–	–	–	–	–	–
Hisar	513.2	360.5	42	24.3	54.9	–56
Jhajjar	649.2	394.2	65	44.5	49.3	–8
Jind	462.7	452.5	2	45.2	75.9	–41
Kaithal	500.0	514.7	–3	63.5	82.9	–23
Karnal	411.5	609.7	–32	113.7	122.9	–7
Kurukshetra	392.5	588.8	–33	79.7	106.5	–25

1	2	3	4	5	6	7
Mohindergarh	320.3	444.1	–28	5.4	58.8	–91
Panchkula	1637.8	946.4	73	110.7	167.5	–34
Panipat	287.1	536.6	–47	57	78.7	–28
Rewari	787.8	505.7	56	35.8	53.5	–33
Rohtak	748.3	521.4	44	28.5	79.1	–63
Sirsa	250.6	269.5	–7	10.7	50.8	–78
Sonepat	250.6	546.5	–23	39.0	81.6	–52
Yamunanagar	830.3	936.3	–11	105	171.8	–39
Average	**608.2**	**532.5**	**14**	**52.2**	**84.3**	**–38**

Year 2004

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	1080.2	810.8	33	204.9	145.2	41
Bhiwani	340.6	372.7	–9	189.7	55.3	243
Faridabad	423.8	470.8	–10	236.9	50.3	374
Fatehabad	229.8	322.7	–29	96.9	58.6	64
Gurgaon	407.6	524.2	–22	176.6	58.8	200
Mewat	–	–	–	–	–	–
Hisar	281.1	375.8	–25	152.3	54.9	176
Jhajjar	395.5	393.9	5	130.0	47.6	171
Jind	467.4	452.7	3	201.9	76.4	166
Kaithal	631.8	498.3	27	131.0	87.0	51
Karnal	533.3	602.5	–12	148.9	114.1	32
Kurukshetra	468.9	588.6	–20	159.5	106.5	50
Mohindergarh	206.0	463.5	–56	92.5	58.9	58
Panchkula	674.0	946.8	–29	191.5	165.5	16
Panipat	445.8	536.7	–17	101.0	73.5	36
Rewari	379.8	507.3	–25	121.6	54.4	122
Rohtak	328.2	518.9	–37	148.7	79.2	87
Sirsa	208.0	269.6	–23	121.4	50.8	137
Sonepat	470.6	546.4	–14	189.6	82.2	132
Yamunanagar	745.0	936.5	–20	129.5	172.6	–25
Average	**458.8**	**535.0**	**–14**	**152.8**	**83.6**	**82**

[Sardar H.S. Chatha]

Year 2005

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	943.3	817.6	–15	73.0	144.1	–49
Bhiwani	357.5	372.2	–4	29.0	54.5	–47
Faridabad	519.1	471.1	–10	32.0	53.3	–40
Fatehabad	405.2	317.5	27	48.0	58.5	–19
Gurgaon	575.2	524.4	10	52.0	58.3	–10
Mewat	–	–	–	–	–	–
Hisar	348.7	360.5	–3	29.0	54.2	–46
Jhajjar	531.3	394.0	35	68.0	46.6	45
Jind	702.7	452.6	55	29.0	76.1	–62
Kaithal	639.1	497.9	28	42.0	86.5	–52
Karnal	455.0	609.7	–25	43.0	113.7	–62
Kurukshetra	429.3	558.8	–27	29.0	106.5	–73
Mohindergarh	281.1	443.2	–37	16.0	58.7	–73
Panchkula	669.4	946.4	–29	87.0	164.9	–47
Panipat	485.5	536.6	–10	12.0	73.3	–54
Rewari	534.0	507.1	5	72.0	53.7	33
Rohtak	514.3	521.4	–1	28.0	78.6	–65
Sirsa	213.2	269.3	–21	80.0	50.2	60
Sonepat	464.1	546.7	–15	10.0	81.3	–88
Yamunanagar	872.4	936.3	–7	54.0	171.6	–69
Average	**523.2**	**532.3**	**–2**	**43.8**	**83.3**	**–47**

Year 2006

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	581.4	826.2	–30	341.8	144.1	138
Bhiwani	297.1	372.7	–20	95.9	54.5	75
Faridabad	227.0	470.8	–52	91.1	53.3	72
Fatehabad	253.9	317.7	–20	60.3	58.5	3
Gurgaon	261.0	524.2	–50	172.0	58.3	197
Mewat	–	–	–	107.1	58.3	84
Hisar	233.3	360.8	–35	58.3	54.2	8
Jhajjar	316.1	393.2	–20	95.9	46.6	106

1	2	3	4	5	6	7
Jind	315.9	452.7	–30	167.3	76.1	120
Kaithal	204.0	498.3	–59	116.5	86.5	35
Karnal	271.1	609.5	56	226.2	113.7	98
Kurukshetra	207.3	588.6	–64	208.0	106.5	95
Mohindergarh	132.6	443.5	–70	107.9	58.7	84
Panchkula	659.0	946.8	–30	232.0	164.9	41
Panipat	341.0	536.7	–37	65.3	73.3	–12
Rewari	369.3	507.1	–23	137.2	53.7	154
Rohtak	403.5	521.9	–25	80	78.6	1
Sirsa	336.7	269.6	–47	63.9	50.2	27
Sonepat	290.3	546.4	–47	92.9	81.3	15
Yamunanagar	504.9	936.5	–47	306.0	171.6	78
Average	**326.8**	**532.7**	**–39**	**141.5**	**83.3**	**70**

Year 2007

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	617.5	826.6	–71	18.5	120.1	–85
Bhiwani	240.9	372.2	–35	1.3	46.5	–97
Faridabad	369.2	471.1	–22	0	44.3	–100
Fatehabad	159.1	317.5	–50	16.2	46.5	–65
Gurgaon	266.6	530.4	–50	0	50.3	–100
Mewat	276.1	530.4	–48	0	50.3	–100
Hisar	140.0	360.5	–61	5.3	45.2	–88
Jhajjar	293.4	393.3	–25	0	39.6	–100
Jind	303.4	452.6	–33	0	62.1	–100
Kaithal	266.3	497.9	–43	0	69.5	–100
Karnal	382.7	609.7	–37	4.0	94.7	–96
Kurukshetra	275.2	588.8	–55	8.5	85.5	–90
Mohindergarh	233.5	443.2	–47	1.2	49.7	–97
Panchkula	322.5	946.4	–66	8.5	134.9	–94
Panipat	163.6	536.6	–70	0	60.3	–100
Rewari	369.9	507.1	–27	8.8	46.7	–81

[Sardar H.S. Chatha]

1	2	3	4	5	6	7
Rohtak	152.3	521.4	–71	5.5	63.6	–91
Sirsa	156.5	269.3	–42	4.3	40.2	–89
Sonepat	327.0	546.7	–46	0	67.3	–100
Yamunanagar	431.9	936.3	–54	8.6	142.6	–94
Average	**287.5**	**532.7**	**–46**	**4.7**	**68.0**	**–93**

श्री एस० एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 2003 से 2007 तक पूरे जिलों की रेनफॉल की इन्फर्मेशन सदन में रखी है। मैं समय बचाने के लिए नमूने के तौर पर कुछ जिलों की पोजीशन पढ़कर सुनाऊंगा। जिन जिलों में ऐवरेज से माईनस रेनफॉल हुई है उनमें है अम्बाला में 49 परसैंट, भिवानी में 47 परसैंट, जींद में 62 परसैंट। कुछ जिलों में माईनस 100 परसैंट रेनफॉल हुई है और 7-8 जिलों में माईनस 97 परसैंट रेनफॉल हुई है। चूंकि मॉनसून ड्रिफ्ट होकर अपना रूख गुजरात की तरफ कर गया था जिसके कारण हमारे यहां न सर्दियों में बारिश हुई है और न ही गर्मियों में बारिश हुई है और ये परमानैंट फीचर्स है यह कोई एक साल की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जितनी भयानक और अलार्मिंग सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी है, मौसम विभाग है या एग्रीकल्चर विभाग है क्या इन्होंने पिछले 4 सालों में इस बारे में कोई विचार किया है या कोई योजना बनाई है कि जिससे इस स्थिति का मुकाबला किया जा सके?

10.00 बजे **सरदार एच० एस० चट्ठा :** स्पीकर सर, माननीय साथी ने वाजिब बात कही है कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों के दौरान बरसात माईनस में हुई है। बरसात कम होने की स्थिति में एग्रीकल्चर विभाग का यह दायित्व बनता है कि किसानों को घाटा न होने दिया जाये और उन्हें पूरी उपज मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली बोर्ड और सिंचाई विभाग को मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने बहुत मेहनत करके किसानों को सिंचाई के लिए पूरी बिजली और पानी मुहैया करवाया है। बिजली बोर्ड ने 8.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदकर किसानों को सिंचाई के लिए सस्ते रेट पर बिजली उपलब्ध करवाई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सिंचाई विभाग और बिजली बोर्ड की मीटिंग लेकर हिदायतें दी थी कि बरसात की कमी की वजह से किसानों की फसलें नहीं सूखनी चाहिएं। हमारे मुख्यमंत्री जी की हिदायतों की वजह से ही यह संभव हो पाया है कि बरसात की कमी की वजह से भी किसानों की फसलें नहीं सूखी और उन्हें सिंचाई के लिए बराबर बिजली और पानी मिलता रहा। इसके साथ-साथ एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से भी अच्छे सीड किसानों को उपलब्ध करवाये गये। जहां तक मेरे साथी ने एटमोसफियर की बात की है हमारा विभाग एटमोसफियर को नहीं बदल सकता। एटमोसफियर को देखने का काम दूसरे विभाग का है। हमारा काम यह था कि जो सीड पकने में चार-चार, पांच-पांच महीने का समय लेते थे उनके स्थान पर यूनीवर्सिटी ने नये सीड निकाले हैं जो 10-10 दिन, 15-15 दिन या 20-20 दिन का कम समय पकने में लेंगे ताकि किसानों को जल्दी उपज मिले।

श्री एस० एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया। सरकार के एफर्ट्स के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। यह सही है कि किसानों को सरकार की तरफ से पूरी मात्रा में बिजली और पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। मेरे सवाल को कृषि मंत्री महोदय मानसून की तरह ड्रिफ्ट कर गये। मेरा सवाल यह है कि इनका विभाग चार साल से सोया पड़ा है। ये बतायें कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि इस प्रकार के सीड तैयार किए गए हैं जिनके पकने में 10-15 दिन का कम समय लगता है। इस बारे में भी मुझे डाउट है। मैं भी किसान हूं और मुझे इस प्रकार के सीड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा किया भी है तो यह मेरे सवाल का हल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काम रिसर्च करना है और एग्रीकल्चर विभाग का काम कोओरडीनेट करना है। मौसम विभाग भी काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय एजैंसीज भी हैं लेकिन एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से इस प्रकार के सीरियस काम को लाईटली लेना प्रदेश के हित में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आपका पहला सवाल यह है कि पिछले 4-5 साल से मानसून ने अपनी दिशा बदल ली है तथा आपका दूसरा सवाल यह है कि इस कारण से किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं। इस बारे में मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि बरसात कम होने के बावजूद भी इन्होंने किसानों को बिजली और पानी पूरी मात्रा में मुहैया करवाया है।

श्री एस० एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप भी एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं। इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किए और न ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एफर्ट किए। मौसम विभाग से भी कोआरडिनेट नहीं किया गया। अगर इन्होंने कोई योजना बनाई है तो ये बतायें। आने वाले समय में ये इस प्रकार की गंभीर स्थिति से बिना कोई योजना बनाये कैसे मुकाबला करेंगे?

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को इस बारे में कई बार पत्र लिखे हैं। वहां पर एक्सपर्ट बैठे हैं, वे इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। वहां से इन्स्ट्रक्शंज आनी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने जवाब में दर्शाया है कि हरियाणा में पिछले पांच सालों के दौरान बरसात में कमी हुई है। मंत्री जी मानते हैं कि बरसात कम होती है और धान जैसी फसल के लिए 1500 मिली लीटर बरसात की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर विभाग ने साठी की फसल पर रोक लगाकर या अरली राईस वैरायटी पर रोक लगाकर बहुत अच्छा काम किया है और प्रदेश को फायदा पहुंचाया है। क्या मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि धान की ज्यादा फसल न बोई जाये खासकर उन एरियाज में जहां पर नहरी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार उन किसानों को कोई स्कीम बनाकर देगी जो धान की बिजाई नहीं करेंगे या किसी और तरह से उनको कम्पनसेट किया जायेगा? कृपया इस बारे में मंत्री जी जानकारी दें।

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हर साल 10-15 फुट पानी का लैवल नीचे जा रहा है। यही कारण था कि सरकार द्वारा डबल क्रोपिंग धान पर प्यार सुपरबंदी लगाई गई है न कि कानून सुपरबंदी लगाई है। हमारी सरकार ने किसानों को प्यार से समझाया है कि यह बात उनके हित में नहीं है इसीलिये किसानों ने साठी को छोड़ा है। बाकी जहां तक माननीय साथी ने पैडी को कम करने की बात कही है मैं पर्सनली तौर पर इस बात के हक में हूं कि पैडी की फसल में थोड़ी-बहुत कमी जरूर हो। लेकिन जब तक किसान को कोई अलटरनेटिव नहीं मिलता जितना पैसा किसान को पैडी से मिलता है उतना पैसा उसे किसी और क्रॉप से नहीं मिलता तब तक यह पैडी की फसल कम नहीं होगी।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अम्बाला और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है वह सिंचाई के मामले में पूरी तरह से ट्यूबवैल्स पर निर्भर है। कोई नहर इस इलाके में नहीं है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हमने बहुत बिजली दी है। आज यमुनानगर जिले में गन्ने की बहुत पैदावार होती है उसमें से ज़मीनदारों का 50 प्रतिशत गन्ना पानी न मिलने की वजह से बिल्कुल खत्म हो गया है। बिजली 24 घंटे में सिर्फ दो या ढ़ाई घंटे से ज्यादा पहले भी नहीं मिली और अब भी नहीं मिल रही है। तो क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस बारे में क्या किया जा रहा है क्योंकि अब फसल पकने के मौके पर है।

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त सढ़ौरा साहब मुझे हर रोज़ यहां पर मिलते हैं लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे यह नहीं बताया कि उनकी फसल सूख गई है। मैं मशकूर हूं इनका। जहां तक इन्होंने कहा है कि हमारे यहां नहर नहीं है। तो मैं इनको पूछना चाहूंगा कि इनके यहां नहर कहां नहीं है? यमुनानगर के पास सारी नहरें हैं और जो नग्गल लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम है वह भी है। 6 नहरें तो मैंने तब बनाई थी जब मैं मंत्री था। आपके यहां नहरें भी हैं और आपके यहां ट्यूबवैल्ज़ भी हैं। बहुत ज्यादा एरिया ऐसा है जहां पर सिंचाई का कार्य केवल ट्यूबवैल्ज़ के ऊपर निर्भर है तो वहां भी हमने क्रॉप को नुकसान नहीं होने दिया है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, बहुत वाजिब सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है। यमुनानगर और अम्बाला के जो हमारे इलाके हैं वहां पर ट्यूबवैल्ज़ ही सिंचाई के मुख्य साधन हैं इसमें वर्षों से सरकारों ने वायदे तो किए परन्तु अण्डर ग्राऊण्ड वाटर टेबल रिचार्ज हो और पानी का लैवल ऊपर आये इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था और माननीय सदस्य अगर उस समय मौजूद होते तो शायद आज यह प्रश्न ही न आता। तो जो हमारी शाहाबाद-दादूपुर-नलवी योजना है अध्यक्ष महोदय, It is for recharge of underground water table. पिछले 20 साल से यह कागजों पर थी। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया। इस समय इसका 60 प्रतिशत अर्थ वर्क पूरा हो गया है और 30 प्रतिशत पक्का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। सरकार इस परियोजना पर 267 करोड़ रुपए खर्च करेगी और यह पूरे इलाके की वाटर टेबल को ऊपर उठायेगी। It is not an irrigation Canal. In its sense, it is for recharge of underground water table of your district.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने इस नहर का शिलान्यास पत्थर तो रख दिया था लेकिन एक नया पैसा भी उन्होंने बजट में इसके निर्माण के लिए नहीं रखा और न ही ज़मीन एक्वायर की थी। अब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने यह परियोजना चालू की। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारा जो रेतीला एरिया है इस बार उसमें सरसों की 80-90 प्रतिशत फसल पाले के कारण पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इसके लिए किसान को राहत के तौर पर कुछ मुआवजा देंगे। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जैसा कि हमारी सरकार फसलों के अच्छे बीज किसानों को देती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बीज अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी होगी लेकिन इसमें ऐसा होता है कि बीज फसल की बिजाई का समय निकल जाने के बाद मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे तारा-मीरा, चना और दूसरी फसलों के बीज बिजाई के समय किसानों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करें।

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं और मैं फर्मली हाऊस में भी यह बात कह सकता हूं कि हमने किसान को बीज जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की है। किसान को बीज मिलने में देरी हुई हो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह भान : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने माननीय साथी सुरजेवाला जी के जवाब में डाइवर्सिफिकेशन की बात कही है। डाइवर्सिफिकेशन की बात लम्बे अर्से से की जा रही है और यह वैलिड बात भी है कि जहां पर पानी की कमी है वहां पर हम क्या कर रहे हैं? हमारे इलाके में साठी जीरी लगाई जाती थी। मुख्यमंत्री जी ने कई बार साठी जीरी की बुआई को छोड़ने के लिए कहा तो लोगों ने छोड़ दी लेकिन उससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि जीरी 20-25 हजार रुपए की होती थी और फिर दूसरी फसल भी बोई जा सकती थी। इस तरह से कहीं न कहीं तो यूनिवर्सिटीज का ही दोष है कि कृषि में इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी वे कुछ नहीं दे पा रही हैं।

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि यह फसलों की डाइवर्सिफिकेशन की जो आपने बात कही है यह बिल्कुल सही है। दूसरी फसलों में इतना पैसा नहीं होता है जितना कि जीरी में होता है। अब की बार जो जीरी हुई है वह कई जगह तो एक एकड़ में 45-50 हजार रुपए तक हुई है जबकि दाल निकलती है 7-8 हजार रुपए की। यह बात सही है कि किसान को रिम्यूनेरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए लेकिन किसान को पूरी कीमत नहीं मिल पाती। जब तक किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती तब तक डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। डाइवर्सिफिकेशन के कारण हमने एक बार सोयाबीन लगवाई थी। वह सोयाबीन किसी ने नहीं खरीदी। जालन्धर की मण्डी में जाकर

[सरदार एच० एस० चट्ठा]
वह सोयाबीन बिकी थी। यह बात आपकी पूरी तरह से ठीक है कि 25 परसैंट जीरी कम होनी चाहिए लेकिन इसका अलटरनेट आज के दिन हिन्दुस्तान में नहीं है।

Enhancement in the Sandy Area Water Allowance

***940. Sh. Nirpender Singh Sangwan :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the sandy area water allowance from 2.4 per thousand acre area to 3.4 per thousand acre area for the area falling under the Loharu Lift Irrigation Canal System ; if so, the time by which the above said proposal is likely to be implemented ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No Sir, However, Government has restored the water allowance for the Loharu Lift Irrigation Canal System to 3.05 cusecs per thousand acres of the culturable commanded area at outlet head.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या अभी तक हमें जो पानी मिल रहा है वह 2.4 क्यूसिक के हिसाब से ही वे दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जवाब में बता तो दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो लिफ्ट कैनाल उन सैंडी एरियाज में हैं जहां पर लिफ्ट से उठाकर पानी जाता है, उन सैंडी एरियाज में जब इस लिफ्ट कैनाल को बनाने की प्रपोजल बनाई गई उस समय 3.05 क्यूसिक पानी प्रति हजार एकड़ के हिसाब से देने की बात की गई थी। लाइट चली जाती है तो पानी वापिस चला जाता है इससे काफी दिक्कत होती है। जैसा मैंने बताया कि पिछली सरकार के इन लोगों ने अच्छा काम तो कोई किया नहीं। 2003 में इन्होंने जे०एल०एन० महेन्द्रगढ़ और लोहारू कैनाल में जो कमांड एरिया है उसका 3.05 से 2.4 क्यूसिक पानी प्रति हजार एकड़ कर दिया यानी कम कर दिया। एक तरफ तो भाखड़ा वाटर सर्विसिज का जो कमांड एरिया है वह 80 परसैंट इरीगेशन है, डब्ल्यू०वाई०सी० के अन्दर 65 परसैंट है और दूसरी तरफ हमारे यहां जहां कि लिफ्ट इरीगेशन एरियाज हैं, वहां पर 8 परसैंट इरीगेशन एरिया है। इनके ये हालात हैं कोई अच्छा काम करने की बजाय उसको ये उल्टा करते हैं। मौजूदा सरकार में श्री सोमबीर सिंह जी ने प्रश्न पूछा था कि इनके एरिया को 3.05 क्यूसिक पानी प्रति हजार एकड़ के हिसाब से दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा। उसका बाकायदा डिपार्टमैंट ने पूरा अध्ययन किया और उसके बाद रिसैंटली हमने 3.05 क्यूसिक पानी प्रति हजार एकड़ के हिसाब से किया है जिसकी वजह से लिफ्ट इरीगेशन का हमारा तकरीबन 25 परसैंट शेयर बढ़ेगा। सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं जैसे बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक ब्रांच का 98 परसैंट काम पूरा हो चुका है। एस०वाई०एल० का अभी हमें पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह केस

सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है जिसकी वजह से हमें पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। पंजाब से हमें भाखड़ा से आगे मूनक पर जो पानी मिलता है वहां भी काफी दिक्कत आती है और हमें पूरा पानी नहीं मिलता है। वहां भी हमारा शेयर 2.4 था और जे०एल०एन० फीडर में दोनों को मिला कर हमारा 3000 क्यूसिक के करीब था उसको घटा कर 1900 क्यूसिक कर दिया था। अब वह बढ़ कर 2405 क्यूसिक हो जाएगा। यानि जिसमें महेन्द्रगढ़ कैनाल, जे०एल०एन० फीडर जिसमें झज्जर के एरिया में लिफ्ट कैनाल है वह बढ़कर 2405 क्यूसिक हो जाएगा। 664 क्यूसिक पानी महेन्द्रगढ़ कैनाल सिस्टम में है जिसको दो ग्रुप में चलाया जाएगा। उस वक्त इन्होंने वह 518 क्यूसिक कर दिया था। जे०एल०एन० में 463 क्यूसिक हो जाएगा जिसको घटा कर इन्होंने 328 क्यूसिक कर दिया। उसी प्रकार से लोहारू कैनाल प्रोजैक्ट में 538 क्यूसिक हो जाएगा जो कि दो ग्रुप में चलेगा उसको घटा कर इन्होंने 402 क्यूसिक कर दिया था। स्पीकर सर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतना ही नहीं पानी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दादूपुर नलवी प्रोजैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से शुरू हुआ और उसका श्रेय लेने का प्रयास ये पिछली सरकार के श्रीमान् जी कर रहे हैं और कहते हैं कि इसकी शुरूआत इन्होंने की थी। मात्र पत्थर रख कर चले जाओ, न बजट में पैसे का प्रोवीजन करो, न जमीन ऐक्वायर करो तो नहर कैसे बन जाएगी। हमारी सरकार ने न्यू फ्लोर रेट के हिसाब से जमीन का कम्पनसैशन दिया हैं मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अम्बाला इरीगेशन स्कीम का काम भी हमारी सरकार कर रही है और मेवात कैनाल का काम भी हमारी सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रोजैक्टस के पूरा हो जाने के बाद किसानों को उनका पूरा हक मिलेगा। स्पीकर सर, पीछे कुछ बरसात कम रही और पंजाब से भी पानी कम मिलता रहा है जिसकी वजह से हम पूरा पानी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन हमारी यह कोशिश होगी कि जब रेनी सीजन होगा और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पानी होगा तो हम लोगों को पूरा पानी देंगे।

Construction of Mini Secretariat at Ateli Mandi

*934. **Sh. Naresh Yadav :** Will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini-Secretariat at Ateli Mandi ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : जी नहीं।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, अटेली कस्बा एक ऐसी जगह है जहां पर कोई सरकारी जगह नहीं है। अटेली के पास खोड़ गांव है जहां पर गांव की पंचायत बस स्टैंड के पास जमीन देने को तैयार है। हमारे जितने भी कार्यालय हैं एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर के फासले पर छोटे से कस्बे के चारों तरफ पड़ते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां पर एक मिनी सैक्रेटेरियेट बनाने के बारे में विचार करेगी ताकि सारे सरकारी कार्यालय एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाएं और लोगों को सुविधा हो जाए। इस मिनी सैक्रेटेरियेट के लिए गांव खोड़ में पंचायत ज़मीन देने के लिए भी तैयार है, क्या वहां पर मिनी सैक्रेटेरियेट बनाया जाएगा ?

श्रीमती सावित्री जिंदल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि अटेली मण्डी में एक उप-तहसील है और अटेली मण्डी के लोगों के लिए जिला सचिवालय महेन्द्रगढ़ में बना हुआ है। उप-तहसील में उप-तहसील के लिए भवन बनाया जाएगा इसके लिए जमीन आईडैंटिफाई कर रहे हैं, जगह आईडैंटिफाई करने के बाद वहां पर भवन बनाया जाएगा लेकिन उसका काम अभी मार्कीट कमेटी के भवन में चल रहा है।

Misuse of Red Cross Funds

***915. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the State Minister for Revenue and Disaster Management be pleased to state :—

(a) Whether State Government has received any complaint regarding misuse of Red Cross Funds by Deputy Commissioners or any other officer/official since 2000 till date ; and

(b) If so, the contents of such complaints alongwith the action taken on the complaints in (a) above ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) जी हां,

(ख) एक शिकायत समाज कल्याण विभाग से सचिव, जिला रैडक्रॉस शाखा, जीन्द के विरुद्ध प्राप्त हुई थी, जिसका सम्बन्ध एक आडिट पैरा से था जिसमें यह आपत्ति उठाई गई थी कि 15,66,000/- रुपए की लागत से खरीदी गई ट्राईसाईकल आई०एस०आई० मार्का नहीं थी। जांच उपरांत मामला जिला उपायुक्त-कम-प्रधान, जिला रैडक्रॉस शाखा, जीन्द द्वारा दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

एक अन्य शिकायत श्रीमती विजय चौधरी पूर्व सचिव, जिला रैडक्रॉस सोसायटी कैथल, जो वर्तमान में जिला रैडक्रॉस सोसायटी पानीपत में सचिव के पद पर पदस्थ हैं, के विरुद्ध महामहिम हरियाणा के राज्यपाल के कार्यालय से प्राप्त हुई थी। उन्हें आरोपित करके नियमित जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है तथा जांच चल रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे सवाल के पार्ट बी का सही जवाब नहीं दिया है। मैंने यह कहा था—

"If so, the contents of such complaints alongwith the action taken on the complaints in 'a' above."

उनकी जो कम्पलेंट थी उसके कंटैंट सदन के पटल पर नहीं रखे गये हैं और उनके जवाब में भी शामिल नहीं किये गये हैं। उन्होंने लिहाजा यह कहा है कि उनके पास शिकायत थी। मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने पानीपत के लिए कहा, क्या यह सही नहीं है कि उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने रैडक्रॉस के पैसे से मोबाईल फोन खरीदे थे (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पानीपत का जिक्र किया है उसके बारे में अखबारों में भी आता था और कम्पलेंट यह थी कि उन्होंने रैडक्रॉस के पैसे से महंगे मोबाईल खरीदे और उनका दुरुपयोग किया। अध्यक्ष महोदय, उसका बिल भी रैडक्रॉस के पैसे से अदा किया जाता था। क्या इस बारे में मंत्री महोदया जी को जानकारी है? अगर नहीं है तो क्या मंत्री महोदया इस बारे में दोबारा से जांच करवाने की कोशिश करेंगी?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी कर्ण सिंह जी ने जो दोनों कम्पलेंटस के बारे में कन्टैंटस जानने चाहे हैं उस बारे में माननीय मंत्री महोदया दोनों कम्पलेंटस के कन्टैंटस इनको भिजवा देंगी। इन्होंने जो पानीपत के सम्बन्ध में शिकायत की बात की है, इस बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एक कम्पलेंट सैक्रेटरी, डिस्ट्रीक्ट रैडक्रॉस, जीन्द के खिलाफ है। यह कम्पलेंट क्या थी इस बारे में स्पष्ट बताया है कि इसमें 15,66,000 रुपए इन्वालव्ड थे और यह केस फाईल हो चुका है। दूसरी कम्पलेंट एक्स सैक्रेटरी, डिस्ट्रीक्ट रैड क्रॉस सोसाईटी, कैथल को लेकर है। उस बारे में भी हमने जवाब में तथ्य दे दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने पानीपत इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर के बारे में चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय साथी, माननीय मंत्री जी को लिखकर भिजवा दें तो उसकी जांच अवश्य करवाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसमें कोई भी तथ्य छिपाने की जरूरत नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करवाएंगे।

श्री शादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रैडक्रॉस के अकाऊंटस रैगुलर आडिट होते हैं? इसके साथ मंत्री जी यह भी बताएं कि पिछले सालों में डिस्ट्रीक्ट वाईज कितने रैडक्रॉस सोसाईटीज के अकाऊंटस आडिट हुए हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है और माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भिजवा दें तो इनको इसका जवाब लिखकर दे दिया जाएगा।

श्री शादी लाल बत्रा : यह पृथक प्रश्न नहीं है। It is a part of Red Cross. मैंने प्रश्न रैडक्रॉस के अकाऊंटस कैसे मैनटेन किए जाते हैं, के बारे में पूछा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहूंगा कि हर प्रश्न जो रैडक्रॉस की फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है वह इस प्रश्न के अन्दर नहीं आ सकता है। माननीय मंत्री जी के पास इस तरह की हैंडि इन्फर्मेशन नहीं हो सकती है। ये अपने प्रश्न को माननीय मंत्री महोदया को लिखकर भेज दें और इनको उसका जवाब लिखित में दे दिया जाएगा।

Special Exemption to Women on Domestic Electricity Connection

***890. Dr. Sushil Indora :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether any provision of special exemption for the women has been made by the Govt. for releasing domestic electricity connection ;

(b) if so, the number of the women in the State who have benefited from such exemption ; and

(c) whether any increase in the numbers of domestic electricity connection has been reported due to said electricity exemption ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir.

However in compliance to the decision taken by the Govt. of Haryana, concession of 10 paisa per unit for domestic electric connection in the name of women in case that property is owned by women is allowed in the electricity bill.

(b) Question does not arise.

(c) Question does not arise.

डॉ. सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। लेकिन ये पता नहीं किस तरह से इसको क्रियान्वयन कर रहे हैं कि इसको इम्पलीमैंट नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है कि महिलाओं के लिए सरकार 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिलों में फायदा दे रही है। इस बारे में जगह-जगह पर बोर्डज भी लगे हुए हैं। अब इन्होंने जवाब में कह दिया है कि महिलाओं को घरेलू बिजली कनैक्शन देने के लिए विशेष छूट का कोई प्रावधान नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में कहा है "यद्यपि, हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में महिला के नाम पर घरेलू बिजली कनैक्शन लेने पर बशर्ते कि सम्पत्ति की स्वयं मालिक होने पर बिजली बिल में 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है।" अध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होंने प्रावधान के हिसाब से जवाब दे दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर महिलाओं के नाम से प्लॉट नहीं है और यदि वे उसकी स्वामी नहीं है तो इस बारे में भी इनको वर्णन करना चाहिए था। क्या आप इस बारे में बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको मकान की स्वामी होने पर स्वयं कितना लाभ पहुंचा है? साथ में मंत्री जी यह भी बताएं कि ऐसी कितनी लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनको ये लाभ देने जा रहे हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो महिलाओं को लेकर संशय जाहिर की है वह वाजिब है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने महिलाओं के कल्याण को लेकर अनेकों कदम उठाये हैं। जहां तक इन्होंने जो जानकारी चाही है तो इस विषय में इनको बताना चाहूंगा

कि 31 जनवरी, 2008 तक 21,201 महिलाओं ने उत्तरी हरियाणा वितरण निगम में और 35,917 महिलाओं ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में यानि की कुल 57,118 महिलाओं ने इस स्कीम का जिसमें प्रति यूनिट 10 पैसे की छूट है, लाभ उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दस पैसे प्रति यूनिट छूट देने की जो बात की है तो उसके पीछे जो एक सोशल परपज था, जो एक सामाजिक लक्ष्य था उसको मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। इन्होंने जो यह कहा कि महिलाएं जो हैं उनके मकान और सम्पत्ति जो उनके पति की है या पिता की भी है, उसकी मल्कियत के अंदर सही मायनों में हिस्सेदारी बने। स्पीकर साहब, इनको तो इस बात की ताईद करनी चाहिए कि आजादी के 60 साल बाद पहली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार ने महिलाओं को अब तो पैतृक सम्पत्ति के अंदर भी अधिकार दिए हैं। इसके अलावा जो दूसरी महिला कल्याण की योजनाएं हैं उनकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है अगर ये उस समय सदन में होते तो इनको अवश्य ही जानकारी मिल जाती।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें हकीकत यह है कि कुछ शर्तें लगी हुई हैं कि जो मकान है उसकी भी वह स्वयं मालिक होनी चाहिए। स्पीकर साहब, जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश की कल्चर भी है कि ज्यादातर बाप दादा के नाम से जमीन होती है तो क्या सरकार ऐसी छूट देने का भी प्रावधान करेगी कि अगर महिला मकान की मालिक नहीं भी है तो उसको दस पैसे प्रति यूनिट की छूट मिले ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। महिलाएं अगर मकान की स्वामी न भी हों तो भी उनको यह लाभ मिलना चाहिए। स्पीकर सर, गांवों में लाल डोरे में किसी के नाम से मकान नहीं होता तो जिस तरह से दस पैसे प्रति यूनिट की छूट है उसमें तो 100 यूनिटस बिजली खर्च करने पर दस रुपए का ही लाभ होगा और इसके लिए भी वे अपने कागज पत्र भी तैयार नहीं कर पाते। स्पीकर सर, आजकल तो बराबरी का अधिकार मांगा जा रहा है लेकिन बराबरी का न सही तो क्या इसमें परैसेंटेज के हिसाब से 20 परसैंट या 25 परसैंट तक महिलाओं को लाभ पहुंचने का काम सरकार करेगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का सवाल महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है जोकि वाजिब है। इनकी चिंता से मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं। इस सदन को और खास तौर से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को विशेष रूप से इस बात की चिंता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को फिर बताना चाहूंगा कि दस पैसे प्रति यूनिट महिलाओं को जो बिजली के बिल में रियायत दी थी उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही निशाना था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस प्रकार की जो अनूठी स्कीम्ज हैं, उनके चलते मकान की सम्पत्ति की मल्कियत के अंदर वे हिस्सेदार बनें। जैसा मैंने पहले बताया कि 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब जानते हैं कि पैतृक सम्पत्ति में हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली में केवल लड़कों को ही सम्पत्ति की मल्कियत के अंदर अधिकार होते थे लड़कियों को कभी यह अधिकार नहीं मिला था। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार के द्वारा कानून बदलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और एक मुश्त एक झटके से पूरे हिन्दुस्तान में लड़के और लड़कियों को बराबरी

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

में सम्पत्ति की मल्कियत के अधिकार दिए गए। स्पीकर साहब, इसी तरह से हरियाणा में भी महिला कल्याण की अनेकानेक योजनाएं चल रही हैं चाहे लाडली योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शुगन योजना हो, चाहे लिंगानुपात की दर को कम करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए कारगर कदम हों, चाहे महिलाओं के नाम से सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर दो परसैंट की छूट देने की बात हो तथा चाहे दूसरी अन्य कल्याणकारी योजनाएं हों, वह भी सरकार ने शुरू की हैं।

Ponds dug out under the Rojgar Guarantee Yojna

***857. Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the names of the Panchayats by whom the ponds have been dug out under the Rojgar Guarantee Yojna in district Sirsa togetherwith the total amount spent on the digging out a pond ; and

(b) the total amount spent on the all works referred to in Part (a) above in district Sirsa ?

Power Minister (Shri Rendeep Singh Surjewala) : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The names of Panchayats by whom the ponds have been dug under the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) in district Sirsa togetherwith the amount spent thereon are given below.

(b) An amount of Rs. 922.449 lacs have been spent on all the works referred to in Part (a) above in district Sirsa.

The Panchayat-wise details are as under :—

Block : Sirsa

Sr. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Village	No. of pond	Amount Spent (Rs. in lacs)
1	2	3	4	5
1.	Ahmedpur	Ahmedpur	1	0.126
2.	Alanoor/Nanakpur	Alanoor/Nanakpur	1	0.430
3.	Bajekan	Bajekan	3	5.589
4.	Bansudhar	Bansudhar	3	4.275
5.	Baruwali	Baruwali	2	4.303
6.	Bhamboor	Bhamboor	1	1.640
7.	Bharokhan	Bharokhan	4	4.576
8.	Chamal	Chamal	3	6.690

1	2	3	4	5
9.	Darbi	Darbi	1	4.920
10.	Dhani 400	Dhani 400	3	1.456
11.	Dhani Kheowali	Dhani Kheowali	3	1.390
12.	Dhani Rampur	Dhani Rampur	2	0.301
13.	Farwain Kalan	Farwain Kalan	3	3.100
14.	Farwain Khurd	Farwain Khurd	3	2.600
15.	Handi Khera	Handi Khera	4	4.167
16.	Jhompra	Jhompra	2	0.464
17.	Jhorarnali	Jhorarnali	2	1.570
18.	Kanganpur	Kanganpur	2	6.104
19.	Kanwarpura	Kanwarpura	2	3.800
20.	Kasumbi	Kasumbi	1	1.990
21.	Kelnia	Kelnia	1	1.240
22.	Kotli	Kotli	1	7.900
23.	Madhosinghana	Madhosinghana	2	1.287
24.	Mangala	Mangala	2	2.250
25.	Mohmadpur	Mohmadpur	1	0.680
26.	Moriwala	Moriwala	2	3.970
27.	Narel Khera	Narel Khera	2	4.035
28.	Nattar	Nattar	1	1.110
29.	Patli Dabar	Patli Dabar	2	2.810
30.	Phoolkan	Phoolkan	2	1.760
31.	Rasulpur	Rasulpur	2	1.911
32.	Shahidanwali	Shahidanwali	1	1.680
33.	Shahpur Begu	Shahpur Begu	1	1.520
34.	Sikander Pur	Sikander Pur	2	8.718
35.	Suchan	Suchan	3	4.523
36.	Ther B. Sawan Singh	Ther B. Sawan Singh	2	1.454
37.	Vaidwala	Vaidwala	1	2.270
	Total		74	**108.609**
Block : Odhan				
1.	Anandgarh	Anandgarh	1	2.440
2.	Asir	Asir	3	6.180
3.	Chatha	Chatha	1	3.550
4.	Chormar Khera	Chormar Khera	3	3.380
5.	Chukerian	Chukerian	2	5.660
6.	Dadu	Dadu	1	6.590
7.	Desu Malkana	Desu Malkana	2	6,780
8.	Dharampura	Dharampura	1	3.370
9.	Ghukanwali	Ghukanwali	4	8.550

[Shri Rendeep Singh Surjewala]

1	2	3	4	5
10.	Hassu	Hassu	1	1.890
11.	Jagmalwali	Jagmalwali	2	5.300
12.	Jalalana	Jalalana	3	9.800
13.	Jandwala Jattan	Jandwala Jattan	3	7.120
14.	Kalanwali Village	Kalanwali Village	2	7.310
15.	Khatrawan	Khatrawan	2	0.670
16.	Kheowali	Kheowali	2	6.220
17.	Khokhar	Khokhar	1	0.620
18.	Kingre	Kingre	2	3.640
19.	Makha	Makha	2	1.870
20.	Malikpura	Malikpura	3	7.070
21.	Mithri	Mithri	2	4.640
22.	Naurang	Naurang	1	1.580
23.	Nuhianwali	Nuhianwali	1	4.840
24.	Odhan	Odhan	4	9.270
25.	Panniwala Mota	Paniwala Mota	5	11.400
26.	Pipli	Pipli	2	6.650
27.	Salam Khera	Salam Khera	1	1.020
28.	Singhpura	Singhpura	4	7.840
29.	Takhatmal	Takhatmal	1	2.500
30.	Tappi	Tappi	3	6.500
31.	Taruana	Taruana	2	2.320
32.	Tigri	Tigri	2	7.670
33.	Tilokewala	Tilokewala	3	7.310
	Total		**72**	**171.550**
Block : Nathusari Chopta				
1.	Ali Mohamad	Ali Mohamad	2	10.790
2.	Arnianwali	Arnianwali	1	1.900
3.	Bakarianwali	Bakarianwali	1	0.960
4.	Barasari	Barasari	2	5.760
5.	Chadiwal	Chadiwal	4	8.060
6.	Chaharwala	Chaharwala	2	5.050
7.	Chauburja	Chauburja	2	6.780
8.	Darba Kalan	Darba Kalan	1	1.940
9.	Dhingtania	Dhingtania	1	3.500
10.	Dhookra	Dhookra	1	5.680
11.	Ding	Ding	2	8.400
12.	Gadli	Gadli	1	1.900
13.	Ganja Rupana	Ganja Rupana	2	6.200
14.	Gigorani	Gigorani	2	4.600
15.	Gudia Khera	Gudia Khera	2	9.000
16.	Gusain Wala	Gusain Wala	1	2.500

1	2	3	4	5
17.	Hanjira	Hanjira	2	4.750
18.	Jamal	Jamal	2	4.540
19.	Jasania	Jasania	2	1.300
20.	Jodhakan	Jodhakan	2	5.250
21.	Jogiwala	Jogiwala	2	5.120
22.	Jorian	Jorian	1	6.370
23.	Kagdana	Kagdana	2	5.000
24.	Kheri	Kheri	1	4.900
25.	Kukarthana	Kukarthana	1	2.900
26.	Kumharia	Kumharia	2	8.900
27.	Kutiana	Kutiana	2	4.150
28.	Ludesar	Ludesar	2	3.730
29.	Makhosarani	Makhosarani	1	1.900
30.	Mochiwali	Mochiwali	2	6.000
31.	Modia Khera	Modia Khera	2	2.650
32.	Nathusari Kalan	Nathusari Kalan	1	6.200
33.	Neharana	Neharana	3	10.050
34.	Nejia Khera	Nejia Khera	1	1.700
35.	Nirban	Nirban	3	5.650
36.	Raipur	Raipur	1	3.820
37.	Rajpura Keranwali	Rajpura Keranwali	1	0.800
38.	Rajpura Sahni	Rajpura Sahni	1	2.000
39.	Rampura Bagrian	Rampura Bagrian	1	0.400
40.	Rampura Dhillon	Rampura Dhillon	1	2.000
41.	Randhawa	Randhawa	2	5.100
42.	Rupana Bishonia	Rupana Bishonia	1	0.500
43.	Rupana Khurd	Rupana Khurd	1	1.000
44.	Rupawaas	Rupawaas	1	4.950
45.	Sahuwala-II	Sahuwala-II	1	1.200
46.	Shahpuria	Shahpuria	2	7.450
47.	Shakkar Mandori	Shakkar Mandori	2	6.800
48.	Sherpura	Sherpura	1	2.500
49.	Tajia Khera	Tajia Khera	1	2.500
50.	Tarkanwali	Tarkanwali	1	4.700
	Total		79	**219.800**
Block : Baragudha				
1.	Alikan	Alikan	1	2.880
2.	Bhadra	Bhadra	1	1.440
3.	Bhangu	Bhangu	2	5.870
4.	Biruwala Gudha	Biruwala Gudha	1	3.680
5.	Bupp	Bupp	1	1.370
6.	Burj Bhangu	Burj Bhangu	2	3.470
7.	Burj Karamgarh	Burj Karamgarh	1	1.280

[Shri Rendeep Singh Surjewala]

1	2	3	4	5
A/8.	Chhatriyan	Chhatriyan	1	1.030
9.	Daulatpur Khera	Daulatpur Khera	2	4.390
10.	Dhaban	Dhaban	1	0.850
11.	Fatehpur Niyamat	Fatehpur Niyamat	3	6.800
12.	Jhiri	Jhiri	2	2.380
13.	Jhorar Rohi	Jhorar Rohi	2	4.000
14.	Kamal	Kamal	1	0.700
15.	Karamgarh	Karamgarh	2	3.360
16.	Khai Shergarh	Khai Shergarh	3	8.020
17.	Khuiyan Nepalpur	Khuiyan Nepalpur	2	3.080
18.	Kuranganwali	Kuranganwali	2	2.270
19.	Malari	Malari	3	0.990
20.	Mallenwala	Mallenwala	4	7.850
21.	Mattar	Mattar	1	2.380
22.	Nagoki	Nagoki	1	1.750
23.	Nezadela Khurd	Nezadela Khurd	3	2.390
24.	Panjuana	Panjuana	2	4.460
25.	Pucca	Pucca	1	2.350
26.	Raghuana	Raghuana	1	6.570
27.	Ranga	Ranga	1	0.590
28.	Rohan	Rohan	1	1.190
29.	Rori	Rori	2	0.550
30.	Saharni	Saharni	1	0.750
31.	Sahauwala-I	Sahauwala-I	3	3.490
32.	Shekhupuria	Shekhupuria	3	4.310
33.	Subewala Khera	Subewala Khera	2	3.050
34.	Sukhchain	Sukhchain	4	3.430
35.	Surtia	Surtia	2	2.300
36.	Thiraj	Thiraj	1	0.920
	Total		**66**	**106.190**
Block : Dabwali				
1.	Abubsahar	Abubsahar	1	2.900
2.	Ahmadpur Darewala	Ahmadpur Darewala	4	26.300
3.	Alikan	Alikan	1	8.800
4.	Assa Khera	Assa Khera	2	2.850
5.	Banwala	Banwala	1	7.000
6.	Bharu Khera	Bharu Khera	2	6.300
7.	Bijuwali	Bijuwali	2	1.750
8.	Chakjallu	Chakjalu	1	2.200
9.	Desujodha	Desujodha	1	2.400
10.	Ganga	Ganga	6	9.600
11.	Goriwala	Goriwala	1	3.450

1	2	3	4	5
12.	Jandwala Bishnoia	Jandwala Bishnoia	1	6.500
13.	Jhutti Khera	Jhutti Khera	1	2.000
14.	Jogawala	Jogawala	1	1.400
15.	Juttanwali	Juttanwali	1	4.500
16.	Kaluana	Kaluana	2	7.070
17.	Khuian Malkana	Khuian Malkana	2	4.400
18.	Lohgarh	Lohgarh	1	2.700
19.	Mangeana	Mangeana	1	1.950
20.	Mathdadu	Mathdadu	1	4.300
21.	Modi	Modi	1	6.100
22.	Moonawali	Moonawali	2	3.900
23.	Panniwala Morikan	Panniwala Morikan	1	2.700
24.	Panniwala Ruldu	Panniwala Ruldu	1	1.000
25.	Phullo	Phullo	2	2.100
26.	Rajpura	Rajpura	1	1.700
27.	Ramgarh	Ramgarh	1	3.500
28.	Rampura Bishnoia	Rampura Bishnoia	2	6.100
29.	Ratta Khera	Ratta Khera	1	4.000
30.	Risalia Khera	Risalia Khera	1	4.000
31.	Sakta Khera	Sakta Khera	1	4.000
32.	Sawant Khera	Sawant Khera	1	1.380
33.	Shergarh	Shergarh	3	5.720
34.	Teja Khera	Teja Khera	1	2.400
	Total		**52**	**156.970**
Block : Rania				
1.	Bacher	Bacher	1	1.400
2.	Bahiya	Bahiya	2	2.840
3.	Bani	Bani	2	4.110
4.	Bhoona	Bhoona	1	1.450
5.	Chakan	Chakan	3	8.600
6.	Dariawala Bukharakh	Dariawala Bukharakh	1	0.220
7.	Dhamora Theri	Dhamora Theri	1	0.260
8.	Dhanibangi	Dhanibangi	1	0.110
9.	Dhanoor	Dhanoor	1	2.410
10.	Dhottar	Dhottar	1	1.010
11.	Dhudianwali	Dhudianwali	1	4.000
12.	Fatehpuria	Fatehpuria	1	1.170
13.	Gindran	Gindran	1	2.100
14.	Gobindpura	Gobindpura	1	0.340
15.	Haripura	Haripura	1	1.330
16.	Jodhpuria	Jodhpuria	2	5.280
17.	Keharwala	Keharwala	2	5.030
18.	Khaja Khera	Khaja Khera	1	0.510

[Shri Rendeep Singh Surjewala]

1	2	3	4	5
19.	Kussar	Kussar	2	1.680
20.	Mamber Khera	Mamber Khera	3	5.930
21.	Mangalia	Mangalia	1	1.230
22.	Mattu Wala	Mattu Wala	1	0.840
23.	Mehna Khera	Mehna Khera	2	2.790
24.	Mohmadpuria	Mohmadpuria	1	1.300
25.	Moujdeen	Moujdeen	1	0.200
26.	Naiwala	Naiwala	1	0.980
27.	Nakora	Nakora	1	1.700
28.	Nathor	Nathor	3	5.140
29.	Ottu	Ottu	1	1.110
30.	Patti Rathawas	Patti Rathawas	2	6.860
31.	Peer Khera	Peer Khera	2	3.170
32.	Rampur Ther	Rampur Ther	1	0.450
33.	Ranjitpur Their	Ranjitpur Their	0	0.000
34.	Sadewala	Sadewala	1	0.710
35.	Sainpal	Sainpal	2	2.260
36.	Sultanpuria	Sultanpuria	3	4.050
37.	Their Mohar Singh	Their Mohar Singh	1	1.180
38.	Ther Shahidanwali	Ther Shahidanwali	1	2.420
	Total		**54**	**86.170**
Block : Ellenabad				
1.	Amritsar Kalan	Amritsar Kalan	2	1.970
2.	Bhuratwala	Bhuratwala	2	4.870
3.	Dhani Bachan Singh	Dhani Bachan Singh	1	1.620
4.	Dhani Jattan	Dhani Jattan	3	2.340
5.	Dhani Kahan Singh	Dhani Kahan Singh	1	0.170
6.	Dhani Mauju	Dhani Mauju	1	2.790
7.	Dhani Sheran	Dhani Sheran	2	4.480
8.	Dharampura	Dharampura	1	2.290
9.	Jiwan Nagar	Jiwan Nagar	1	1.550
10.	Karam Shana	Karam Shana	2	5.340
11.	Kariwala	Kariwala	1	1.590
12.	Kashi Ram Ka Bass	Kashi Ram Ka Bass	1	3.130
13.	Kheri Surera	Khari Surera	2	7.450
14.	Kotli	Kotli	1	0.480
15.	Kumthala	Kumthala	1	0.200
16.	Mamera Kalan	Mamera Kalan	2	3.960
17.	Mamera Khurd	Mamera Khurd	1	1.000
18.	Mauju Khera	Mauju Khera	1	1.230
19.	Mirzapur	Mirzapur	2	1.390
20.	Mithanpura	Mithanpura	3	2.520

1	2	3	4	5
21.	Mithi Sureran	Mithi Sureran	3	2.470
22.	Neemla	Neemla	1	3.670
23.	Partap Nagar	Partap Nagar	4	4.680
24.	Poharkan	Poharkan	1	0.970
25.	Talwara Khurd	Talwara Khurd	2	7.510
26.	Umedpura	Umedpura	2	3.490
	Total		**44**	**73.160**
	District Total		**441**	**922.449**

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने देखा भी होगा क्योंकि जवाब उनको भी सर्कुलेट हुआ है। केवल सिरसा जिले के अंदर ही अकेले तालाब की खुदाई के एक मद में 441 गांव लाभान्वित हुए और सरकार ने इस काम पर 922 लाख 44 हजार 900 रुपए खर्च किए हैं। स्पीकर सर, सरकार ने जो वहां पर पक्षपात रहित कारगर उठाए हैं यह उसका जीता जागता प्रमाण है।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन जिलों में काम शुरू किया गया है उनमें सिरसा जिला भी एक है। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत गांवों के अंदर जो तालाब खुदवाए गए या तो वह पंचायत की उपजाऊ भूमि पर खुदवाए गए या जहां पर पानी पहुंचने के साधन नहीं हैं ऐसी जगहों पर तालाब खुदवाए गए। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि सरकार मामले की जांच कराएगी क्योंकि एक तो इससे पंचायत का नुकसान हुआ है, उनकी आमदनी घटी है और दूसरे इस तरह से तालाब खुदने का कोई फायदा भी नहीं हुआ है? अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनमें से बहुत से मजदूर हमें यह शिकायत करते हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिली है। इस बारे में क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि.....

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Indira Gandhi Paiy Jal Yojna

***839. Sh. Shamsher Singh Surjewala :** Will the Water Supply & Sanitation Minister be pleased to state :—

(a) whether Haryana Government had launched "Indira Gandhi Paiy Jal Yojna" from 19.11.2006 ;

[Sh. Shamsher Singh Surjewala]

(b) if so, the names and number of the Villages covered under the said Yojna in the Kaithal Assembly constituency ; and

(c) the time by which all the villages in Kaithal Assembly constituency are likely to be covered ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सदन के पटल पर एक स्टेटमैंट रखी है ।

(ग) कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में 30.6.2008 तक कार्य पूरा होने की संभावना है ।

स्टेटमैंट

कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत सम्पन्न किए गए गांवों की स्थिति

क्र.सं.	गांव का नाम	इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत स्थिति
1.	अटेला	कार्य पूरा हो चुका है ।
2.	लडाना बाबा	कार्य पूरा हो चुका है ।
3.	बलवन्ती	कार्य पूरा हो चुका है ।
4.	छोत	कार्य पूरा हो चुका है ।
5.	ढोढ खेड़ी	कार्य पूरा हो चुका है ।
6.	दिलुवाला	कार्य पूरा हो चुका है ।
7.	डावल	कार्य पूरा हो चुका है ।
8.	डोहर	कार्य पूरा हो चुका है ।
9.	ढुडरहेड़ी	कार्य पूरा हो चुका है ।
10.	फरांसवाला	कार्य पूरा हो चुका है ।
11.	गढ़ी पाडला	कार्य पूरा हो चुका है ।
12.	गियोंग	कार्य पूरा हो चुका है ।
13.	गुहना	कार्य पूरा हो चुका है ।
14.	जगदीशपुरा	कार्य पूरा हो चुका है ।
15.	जसवन्ती	कार्य पूरा हो चुका है ।
16.	क्योड़क	कार्य पूरा हो चुका है ।

क्र.सं.	गांव का नाम	इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत स्थिति
17.	खानपुर	कार्य पूरा हो चुका है।
18.	खुराना	कार्य पूरा हो चुका है।
19.	कुलतारन	कार्य पूरा हो चुका है।
20.	माधो भाजरी	कार्य पूरा हो चुका है।
21.	मानस	कार्य पूरा हो चुका है।
22.	पाडला	कार्य पूरा हो चुका है।
23.	पट्टी डोगरान	कार्य पूरा हो चुका है।
24.	कुतबपुर	कार्य पूरा हो चुका है।
25.	फर्श माजरा	कार्य पूरा हो चुका है।
26.	शेरगढ़	कार्य पूरा हो चुका है।
27.	टीक	कार्य पूरा हो चुका है।
28.	उझाना	कार्य पूरा हो चुका है।
29.	धर्मपुरा (एन०सी०)	कार्य पूरा हो चुका है।
30.	देवीगढ़	कार्य पूरा हो चुका है।
31.	बरोट	कार्य प्रगति पर है।
32.	मानपुरा	कार्य प्रगति पर है।
33.	दयोहरा	कार्य प्रगति पर है।
34.	पट्टी अफगान	कार्य अलाट कर दिया है।
35.	पट्टी खोट	कार्य अलाट कर दिया है।
36.	रोहेरियां	कार्य अलाट कर दिया है।
37.	सेरता	कार्य अलाट कर दिया है।

Level of Pollutants in Agra and Gurgaon Canal

***883. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Environment be pleased to state —

(a) the level of pollutants received at head of Agra and Gurgaon canal at Okhla in all four seasons of 2007-08 ; and

(b) the status of pollutants at Faridabad and Palwal of the above canals during the same period as in (a) above ?

वन एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : (क) एवं (ख) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[श्रीमती किरण चौधरी]

विवरण

(क) 2007-08 की सभी चार सीजनों में ओखला में आगरा तथा गुड़गांव नहर हैड पर उपलब्ध प्रदूषण का स्तर बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी०ओ०डी०) के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुज्ञेय सीमाओं के विरुद्ध 13-37 मिलीग्राम प्रति लीटर की रेंज में है। दोनों नहरों में ओखला में बी०ओ०डी० का उच्च स्तर का मुख्य कारण देहली प्रदेश में 22 नहरों के माध्यम से बिना साफ किये/आंशिक साफ किए/औद्योगिक/सीवरेज मलों का यमुना नदी में प्रवाहित करना है।

(ख) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मोनिटरिंग के अनुसार गुड़गांव नहर में बी०ओ०डी० के सन्दर्भ में बदरपुर बोर्डर पर प्रदूषण का स्तर 21-27 मिलीग्राम प्रति लीटर के रेंज में है तथा फरीदाबाद गुड़गांव बोर्डर के समीप गांव बीजूपुर पर बी०ओ०डी० का स्तर 19-26 मिलीग्राम प्रति लीटर की रेंज में है तथा हरियाणा यू०पी० बोर्डर पर गांव करमान के समीप बी०ओ०डी० स्तर 17-19 मिलीग्राम प्रति लीटर की रेंज में है।

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : I have received a Leave of Absence dated 17th March, 2008 from Shri Balbir Pal Shah, M.L.A. which reads as under :—

"Sir,

I humbly request that leave be granted to me in this Session as per recommendations of the Doctor. The Doctor's advice and certificate is attached herewith."

Mr. Speaker : Question is —

That the Leave of Absence be granted to Shri Balbir Pal Shah, M.L.A. to remain absent from the sittings of the House during this Session.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried.

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट में संशोधन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a communication dated 17th March, 2008 from the Government that the Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2007-08 which was to be taken up on 28th March, 2008 may be taken up on 19th March, 2008.

As per the Report of Business Advisory Committee adopted in the House on 7th March, 2008, the Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2007-08 which was to be taken up on 28th

March, 2008, now with the sense of the House, this item of Business may be taken up on 19th March, 2008 and the Report of Business Advisory Committee may be amended and adopted accordingly.

Is it the pleasure of the House to amend the Report of the Business Advisory Committee accordingly ?

Voices : Yes, yes.

(The report was amended and adopted with the sense of the House accordingly.)

वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2008-09.

वित्त मंत्री (श्री बिरेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिये बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वर्ष 2005 में दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद यह कांग्रेस सरकार का लगातार चौथा बजट है।

2. हरियाणा के मतदाताओं द्वारा 2005 में शासन की बागडोर कांग्रेस पार्टी को सौंपे जाने के बाद हमारे प्रयास सतत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने के रहे हैं। मैं सदन का ध्यान जून, 2005 में प्रस्तुत अपने बजट भाषण की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें मैंने कहा था-- "हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम लोगों को स्वच्छ एवं कल्याणकारी शासन प्रदान करके उनमें विश्वास की भावना पैदा करें, जिससे उन्हें भय, आतंक और असुरक्षा से राहत मिलेगी।" मैं आज इस गरिमामय सदन में गर्व के साथ दावा कर सकता हूं कि हमारी सरकार अपने इन लक्ष्यों पर खरी उतरी है और पूर्ण रूप से कानून का शासन स्थापित किया गया है। प्रदेश में शान्ति, सामंजस्य और सामाजिक सद्भावना कायम है। प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आ रही है और वित्तीय दृष्टि से हमारा राज्य देश के सर्वाधिक सुव्यवस्थित राज्यों में से एक है।

3. मैं सदन का ध्यान अपने 2005-06 के बजट भाषण की ओर पुनः दिलाना चाहूंगा, जिसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया था कि राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए पिछली सरकार की कोई विस्तृत दीर्घकालिक नीति न होने की वजह से कांग्रेस सरकार को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा ; संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अर्थोपायों की खोज करनी है और भविष्य में संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु श्रम का पुनः आबंटन करना है। ऐसा करके ही हमारी प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी हो सकती हैं। हमारी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में वर्णित कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं पर पिछले तीन बजटों में समुचित रूप से बल दिया गया है और इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना, उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, सामाजिक क्षेत्र, विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर बल देना

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

और सुदृढ़ आधारभूत ढांचा तैयार करना--ये सब गत तीन वर्षों के दौरान हमारी प्राथमिकताएं रही हैं, जिनके लिए हमने रोड मैप तैयार किया था। अब लक्ष्यों को पूरा करने और लाभों को समुचित रूप से संचित करने का समय आ गया है। हमारे द्वारा इस वर्ष और अगले वर्ष किए जाने वाले प्रयासों से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक विकास की गाथा अल्पकालिक और अस्थाई न होकर शाश्वत व चिरकालिक सच्चाई हो। ये खोखले नारे अथवा दिखावा मात्र नहीं है। हमने आर्थिक विकास की सुदृढ़ नींव रखी है। हमारा वित्तीय प्रबन्धन कौटिल्य द्वारा लिखित 'अर्थशास्त्र' के इन सिद्धान्तों पर आधारित है-- "राज्य की सभी गतिविधियां प्रथमतः खजाने पर निर्भर हैं। इसलिए, एक राजा को इसकी ओर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिये। जिस राजा का खजाना खाली होता है, वह नागरिकों और देश को तबाह कर देता है। अर्थ (सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म और कर्म दोनों ही इस पर निर्भर हैं..... यदि प्राप्तियों और खर्च पर समुचित ध्यान दिया जाये तो राजा को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।"

4. महोदय, हम सही रास्ते पर हैं और हमने राज्य के लिये एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन की नींव रख दी है, जो राज्य के चहुंमुखी विकास के लिये शुभ संकेत है।

आर्थिक परिदृश्य

5. वर्ष 2007-08 के दौरान अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर 101319 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है, जो पिछले वर्ष के त्वरित अनुमानों से 10.1 प्रतिशत अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर वृद्धि वर्ष 2005-06 में 9.2 प्रतिशत और 2006-07 में 11.4 प्रतिशत थी, जो गत दस वर्ष के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर है। वर्ष 2007-08 के दौरान, कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 2.6 प्रतिशत है। चालू वर्ष में उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भवना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों की वृद्धि क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत है।

6. वर्ष 2007.08 में (अग्रिम अनुमान) वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 56,280 रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2006-07 में (त्वरित अनुमान) यह 49038 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय में यह वृद्धि 14.8 प्रतिशत है। वर्ष 2007-08 में (अग्रिम अनुमान) स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर प्रति व्यक्ति आय 38720 रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2006-07 (त्वरित अनुमान) में यह 35779 रुपए थी। यह वृद्धि 7.6 प्रतिशत की राष्ट्रीय वृद्धि के मुकाबले 8.2 प्रतिशत है। आज हरियाणा प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य है।

राजकोषीय प्रबन्धन

7. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ० आर० बी० एम०) अधिनियम, जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन लाना है, को क्रियान्वित करने में अग्रणी है। एफ० आर० बी० एम० अधिनियम में व्यवस्था है कि राज्य को राजस्व घाटा

2008-09 तक शून्य के स्तर पर लाना चाहिये, जबकि मुझे इस गरिमामय सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमने 2005-06 में ही राजस्व अधिशेष प्राप्त करके इस लक्ष्य को बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था। पेंशन, छात्रवृत्तियों, बिजली सबसिडी इत्यादि जैसे राजस्व खर्च के लिये भारी आबंटनों के बावजूद अभी भी राजस्व अधिशेष के दर्जे की प्राप्ति संसाधनों के प्रबन्धन में इस सरकार की विवेकशीलता और अनुशासन का सबूत है।

8. एफ० आर० बी० एम० अधिनियम में व्यवस्था है कि राजकोषीय घाटे को 2008-09 तक कम करके सकल राज्य उत्पाद के तीन प्रतिशत के स्तर पर लाया जाये और गारण्टियों समेत कुल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। परन्तु हमारी सरकार ने एक बार फिर इस निर्धारित लक्ष्य को दो वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। वित्तीय घाटा, जो 2003-04 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत था, को 2006-07 तक कम करके -0.93 प्रतिशत किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान, कुल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.81 प्रतिशत है, जो एफ० आर० बी० एम० अधिनियम की 28 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है।

9. राज्य सरकार राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में एफ० आर० बी० एम० अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके भारत सरकार से ऋण राहत और ब्याज राहत के रूप में दोहरे लाभ प्राप्त कर रही है। राज्य सरकार को 2005-10 के दौरान 581.43 करोड़ रुपए की ऋण राहत प्राप्त होने की सम्भावना है। हमें लाभ मिलने शुरू हो गये हैं और हम यह समस्त लाभ प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। राज्य पर ब्याज का भार, जो 2003-04 में राजस्व प्राप्तियों का 21.46 प्रतिशत था, को घटाकर 2006-07 में कम करके राजस्व प्राप्तियों का 12.62 प्रतिशत किया गया है।

10. हमने खर्च की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। पूंजीगत खर्च, जो परिसम्पत्तियों का निर्माण करता है और जो विकास दर को तेज करता है, 2004-05 में 1105 करोड़ रुपए था। वर्ष 2006-07 में इसमें काफी वृद्धि करते हुए इसे 2612 करोड़ रुपए कर दिया गया और यह 2007-08 के संशोधित अनुमानों में बढ़कर 3386 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में इसे 3751 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का हमारा प्रस्ताव है। राज्य सरकार का शुद्ध ऋण, जो 2003-04 में 2495.24 करोड़ रुपए था, को 2006-07 में काफी कम करके सिर्फ 898 करोड़ रुपए कर दिया गया और 2007-08 में इसकी केवल 46.62 करोड़ रुपए रह जाने की सम्भावना है।

11. 2006-07 के दौरान, राज्य का अपना कुल कर राजस्व पिछले वर्ष से 20.37 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 10928 करोड़ रुपए था। वर्ष 2004-05 के बाद 2006-07 तक राज्य के कर राजस्व में 46.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्वव्यापी मंदी समेत विभिन्न कारणों से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में आई मामूली कमी के बावजूद मुझे इस वर्ष के बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा विश्वास है। हमने 2008-09 के दौरान राज्य कर राजस्व के रूप में 14294 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यह राज्य कर संग्रह में 2007-08 के 12251 करोड़ रुपए के बजट

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

अनुमानों से लगभग 16.88 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि दर्शाता है।

वार्षिक योजना

12. 2006-07 के लिये वार्षिक योजना 3300 करोड़ रुपए की थी, जबकि वास्तविक खर्च 4233 करोड़ रुपए था। वर्ष 2007-08 के दौरान हमारी योजना का आकार 5300 करोड़ रुपए था और मुझे विश्वास है कि वास्तविक योजनागत खर्च 5300 करोड़ रुपए में नहीं बल्कि 5900 करोड़ रुपए से भी अधिक होगा। इस प्रकार, हम अपनी योजना के आकार में साल दर साल वृद्धि कर रहे हैं। योजना आयोग ने 2008-09 के लिये 6650 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की है। योजनागत खर्च, जो पिछली सरकार के शासनकाल में लगभग 2000 करोड़ रुपए पर अटका हुआ था, अब केवल तीन वर्ष में तीन गुणा से भी अधिक बढ़ गया है। गत तीन वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमारी विकास दर ऊंची रही है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस ऊंची विकास दर के बावजूद हमने यह सुनिश्चित किया है कि योजना के आकार और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात, जो कम हो रहा था और जो 2004-05 में मात्र 2.25 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था, को 2007-08 में 3.59 प्रतिशत किया जाये और 2008-09 में इसे और बढ़ाकर 3.85 प्रतिशत किया जायेगा। इस प्रकार हमारी योजनायें न केवल कुल राशि की दृष्टि से बढ़ी हैं, बल्कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की दृष्टि से भी बढ़ी हैं।

13. हमें अनुसूचित जातियों के अपने भाई-बहिनों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, महिलाओं और बच्चों के बारे में गहरी चिन्ता है। हालांकि, अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 19.35 प्रतिशत है, तथापि हमने 2008-09 के दौरान योजनागत परिव्यय की 21.65 प्रतिशत राशि अनुसूचित राशि जातियों के विशेष घटक उप-योजना (एस० सी० एस० पी०) के अन्तर्गत समाज के इस कमजोर वर्ग के कल्याण एवं विकास पर सीधे तौर पर खर्च करने के लिये निर्धारित की है। बी० पी० एल० और अनुसूचित जातियों के पात्र परिवारों को आवासीय प्लाट आवंटित करने की हमारी योजना है। लड़कियों के सामाजिक स्तर में वृद्धि करने की योजनाओं के अतिरिक्त हम "जैंडर बजटिंग" (Gender Budgeting) पर एक विवरण-पत्र (Statement), जो 2008-09 के बजट दस्तावेजों के साथ संलग्न है, भी प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारी सरकार राज्य में समाज केन्द्रित विकास को बढ़ावा देने और विकास के लाभों को समाज के हर स्तर तक पहुंचाने के लिये वचनबद्ध है।

नई पहल

14. अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन में हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिये की गई और की जाने वाली नई शुरूआतों का विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

- कृषि क्षेत्र की विकास दर समग्र रूप से धीमी पड़ गई है और अत्याधिक ग्रामीण कर्जदारी की वजह से हताश व परेशान किसानों द्वारा देश के कई भागों में आत्महत्याएं किए जाने की खबरें आईं।

हम इस अवसर पर यू०पी०ए० अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 2008-09 के केन्द्रीय बजट में छोटे तथा सीमांत किसानों की कर्जदारी को प्रमुखता से उजागर करवाया है। भारत के वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम द्वारा बजट भाषण 2008-09 में समस्त देश के छोटे और सीमांत किसानों के बैंक ऋणों की माफी बारे की गई घोषणा अभूतपूर्व और साहसिक है और यह किसानों की कठिनाइयों को कम करने में काफी मददगार साबित होगी। इससे हमारे राज्य में भी बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे और हम इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम के लिये प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यू० पी० ए० सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे।

लेकिन हम यह भी मानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं, जिन्होंने स्थानीय साहूकारें और आढ़तियों से बहुत ऊंची ब्याज दर पर ऋण ले रखा है। इस समस्या का भी तत्काल समाधान किए जाने की जरूरत है और साहूकारों के इस वर्ग को भी सरकार के प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण के दायरे में लाया जाना चाहिये। ऐसा करके ही इनकी गतिविधियों को समुचित रूप से नियंत्रित व विनियमित किया जा सकता है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र उपचारात्मक उपाय करे।

❖ पिछले बजट में, मैंने कम्पैक्ट फलोरेसैन्ट लैम्पस (सी० एफ० एल०), जो अब उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, पर कर राहत की घोषणा की थी। इनसे बिजली का संरक्षण हो रहा है, जिसकी बहुत जरूरत है। वित्त वर्ष 2008-09 से ऊर्जा की बचत करने वाली ट्यूबों के चोक्स पर भी यह कर राहत देने का मेरा इरादा है।

❖ महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये सेनेटरी नैपकिनस, डायपरज़ और खिलौनों, जिनमें बैटरी चालित बिजली और इलैक्ट्रानिक्स के खिलौने शामिल नहीं हैं, पर वैट समाप्त करने का मेरा प्रस्ताव है। हम सेनेटरी नैपकिनस का उत्पादन करने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रहे हैं।

❖ भूमि और सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टॉम्प शुल्क की दरें 2004 में कम करके शहरी क्षेत्रों में आठ प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 प्रतिशत कर दी गई थीं। सम्पत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम पर करवाये जाने पर हमने इन दरों पर दो प्रतिशत की छूट दी थी। महिलाओं को दी गई इस छूट को जारी रखते हुए स्टॉम्प शुल्क की दरों में एक प्रतिशत की और कमी करने का मेरा इरादा है।

❖ दिल्ली से गुड़गांव तक वाया महरौली मैट्रो रेल लिंक का विस्तार कार्य जोरों पर चल रहा है और इसकी जनवरी, 2010 तक पूरा होने की सम्भावना है। दिल्ली मैट्रो रेल निगम के बोर्ड ने मैट्रो रेल का विस्तार फरीदाबाद तक करने

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

की अनुमति प्रदान कर दी है और बहादुरगढ़ तक इसके विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे हमारे राज्य के एन०सी०आर० क्षेत्र का दिल्ली के साथ सम्पर्क सुगम होगा और इन जिलों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

❖ हमारी सरकार सड़क एवं परिवहन आधारभूत संरचना को अपग्रेड करके राज्य, विशेषतः एन०सी०आर० की संयोजकता में सुधार लाने तथा सामूहिक त्वरित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये हरियाणा सड़क एवं पुल विकास निगम को नोडल एजेंसी नामजद करने पर विचार कर रही है।

❖ हमारा पी०जी०आई० रोहतक में एक हैल्थ यूनिवर्सिटी (Health University) स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके गठन के लिये शीघ्र ही विधानसभा में एक विधेयक लाया जा रहा है। हमने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई०एस०आई०सी०) की वित्तीय सहायता से फरीदाबाद में एक नया स्नातकोत्तर सुविधाओं के साथ एक मैडीकल कॉलेज खोलने का भारत सरकार से आग्रह किया है। हमने इस उद्देश्य के लिये 25 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है और ई०एस०आई० हास्पिटल, फरीदाबाद में पर्याप्त बिस्तर क्षमता उपलब्ध है।

❖ अर्थ-व्यवस्था के विकास को सार्थक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लाभ कुछेक व्यक्तियों तक सीमित न रहकर समाज के सभी व्यक्तियों को बराबर रूप से मिलें। इस दिशा में हमने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 3510 रुपए कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है।

❖ यही नहीं, हमने इस बजट में, सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ देने का प्रयास किया है, जैसा कि हमने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में आश्वासन दिया था। कार ऋण की पात्रता, जो हाल ही में बढ़ाकर पांच लाख रुपए की गई थी, को बढ़ाकर छः लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, गृह ऋण की सीमा 7.5 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए और घर की मरम्मत तथा विस्तार के लिये ऋण सीमा वर्तमान में एक लाख रुपए और 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर क्रमशः दो लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए कर दी है। हमने गेहूं की खरीद के लिये दिये जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण का दायरा भी बढ़ा दिया है। इससे पहले यह ऋण केवल श्रेणी-डी के कर्मचारियों के लिये था। अब यह ऋण श्रेणी-सी के ऐसे कर्मचारियों को भी दिया जायेगा, जिनके मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते की राशि 7000 रुपए प्रतिमास है। यही नहीं, हमने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वेतन तथा पेंशन में होने वाली संभावित बढोतरी के लिये भी वर्ष 2008-09 के बजट में 1550 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है जिसकी रिपोर्ट अगले कुछ ही दिनों में आ सकती है।

❖ आज का युग ज्ञान-विज्ञान का है, जो अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख संचालकों में से एक है। इसलिये विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को अपने अनुसंधान कार्यों के स्तर में सुधार लाने के लिये कमर कसनी होगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि शिक्षकों तथा वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने तथा अपने शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। ऐसे भागीदारों के यात्रा खर्च की 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए शिक्षा विभाग में एक कोष गठित किया जाएगा।

❖ शिक्षा सामाजिक बदलाव और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों के लिये सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने तथा उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम" नामक एक क्रांतिकारी योजना शुरू की गई है। इस योजना से पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर, जो इन वर्गों के बच्चों में सबसे ज्यादा है, में कमी आयेगी। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के सभी छात्रों को 100 रुपए से 300 रुपए प्रतिमास तक तथा सभी छात्राओं को 150 रुपए से 400 रुपए प्रतिमास तक छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को यूनिफार्म, लेखन सामग्री तथा स्कूल बैग इत्यादि के खर्च के लिये भी 740 रुपए से 1450 रुपए तक एक बारगी भत्ता दिया जायेगा। राज्य में बी०पी०एल० परिवारों की सभी छात्राओं को भी यह सुविधा देने का हमारा प्रस्ताव है।

❖ हमारी सरकार ने जिला रिवाड़ी में राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिये ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध करवायेगी और स्कूल चलाने के लिये अनुदान भी देगी।

❖ शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिये उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में विज्ञापन अधिकार नीलाम करने और बिजली के खम्बों का प्रयोग करने वाले केबल आप्रेटरों पर प्रयोगकर्त्ता शुल्क लगाने के लिये प्राधिकृत किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों को ये अधिकार भी दिये जायेंगे कि वे उन केबल आप्रेटरों पर अधिभार लगायें जो अपने केबल नैटवर्क पर वाणिज्यिक विज्ञापन दिखाते हैं।

❖ हमने पंजीकृत बेरोज़गार विज्ञान स्नातकों और स्नातकोत्तरों को 50 प्रतिशत अधिक बेरोज़गारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी बेरोज़गार महिलाओं को भी पुरुषों की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

- सरकार कृषि पम्प सैटों को सस्ती बिजली सप्लाई करने के लिये बिजली निगमों को सबसिडी प्रदान कर रही है। आर०ई० सबसिडी, जो 2004-05 में 1102 करोड़ रुपए थी, वर्ष 2006-07 में बढ़कर 1544 करोड़ रुपए हो गई और जिसकी वर्ष 2007-08 में लगभग 2366 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है। बढ़ती हुई सबसिडी सरकार के लिये एक चिन्ता की बात है और हम किसानों के लाभार्थ ग्रामीण विद्युत सबसिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने पर विचार कर रहे हैं। जिसको डायरेक्ट सबसिडी भी आप कह सकते हैं।

- सरकार अनुसूचित जातियों के लाभानुभोगियों को मकानों के निर्माण के लिये 50,000 रुपए की सबसिडी दे रही है। निर्माण की बढ़ती हुई लागत के दृष्टिगत इन लोगों को इस सबसिडी की राशि से अपना मकान पूरा करने में कठिनाइयां महसूस हो रही है और वे अपने संसाधनों से भी इस उद्देश्य के लिये अतिरिक्त धन जुटाने में सक्षम नहीं है। हमारी सरकार ने एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों के सदस्यों को मकानों के निर्माण के लिये कम ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा। हम इस कार्य में वाणिज्यिक बैंकों को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे।

15. अध्यक्ष महोदय, अब मैं, वर्ष 2008-09 में कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किए गए बजट आबंटन प्रस्तुत करता हूं।

बिजली

16. हमारी सरकार बिजली क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस समय राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 4368 मैगावाट है और उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 739 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है। आगामी पांच वर्ष में बिजली की मांग बढ़कर दुगुनी हो जाने की सम्भावना है। सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि की बिजली सप्लाई करना हमारी विकास नीति की अपेक्षा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये नई पहल की है।

17. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये बिजली उत्पादन संयंत्रों और सम्प्रेषण व वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर 24,317 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार योजना कोष से 20 प्रतिशत इक्विटी उपलब्ध करवायेगी और शेष 80 प्रतिशत राशि बिजली निगमों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में जुटाई जायेगी। हमारी योजना वर्ष 2011 तक बिजली की प्रस्थापित क्षमता में 5000 मैगावाट की वृद्धि करने की है, जो वर्तमान क्षमता से दुगुनी से भी अधिक है। हमें आशा है कि इससे मांग और आपूर्ति का अन्तर समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा, 11वीं योजना के दौरान 1148 मैगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों तथा केन्द्रीय

क्षेत्र की परियोजनाओं से बिजली खरीद समझौते किए गए हैं।

18. यमुनानगर में स्थापित की जा रही 300-300 मैगावाट की दो इकाइयों में से पहली इकाई को नवम्बर, 2007 में सिंक्रोनाईज़ (Synchronize) किया गया तथा दूसरी इकाई को इसी महीने में सिंक्रोनाईज़ (Synchronize) किये जाने की सम्भावना है। हिसार के खेदड़ में 1200 मैगावाट के कोयला आधारित 'राजीव गांधी थर्मल प्लांट' पर भी कार्य शुरू किया जा चुका है और इस प्लांट को वर्ष 2009-10 में चालू किए जाने का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा संयुक्त रूप से जिला झज्जर में 1500 मैगावाट क्षमता का कोयला आधारित एक और थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट वर्ष 2010 में चालू होगा तथा इससे हरियाणा को 750 मैगावाट बिजली मिलेगी। शुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से मातनहेल में 1150 मैगावाट क्षमता का एक और संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

19. अक्षय ऊर्जा नीति के तहत हरेडा ने 697.7 मैगावाट क्षमता की 23 बायो-मास (Bio-mass), तीन लघु पन बिजली तथा चार पवन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से समझौते किए हैं। बायो-मास (Bio-mass) संयंत्रों के मामले में, 75 मैगावाट की सात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की जा चुकी हैं, जबकि 108 मैगावाट की 13 और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनका आकलन किया जाएगा। दस मैगावाट की परियोजना की स्थापना के लिए एक स्थल आबंटित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में समझौते पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त, 4.7 मैगावाट की लघु पन बिजली परियोजनाओं की तीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा एक स्थल पर निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। इसी प्रकार, 340 मैगावाट की पवन बिजली परियोजनाओं की तीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 2008 में प्रस्तुत की जाएंगी तथा सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण एक मामले में प्रक्रिया अभी शुरू की जानी है।

20. 130 मैगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रदेश की सभी चीनी मिलों में हाई प्रैशर बॉयलर्ज एवं टर्बाइन्ज़ (High Pressure Boilers and Turbines) के साथ बिजली सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की भी हमारी योजना है जिसमें से 85 मैगावाट बिजली राज्य बिजली ग्रिड को मिलेगी।

11.00 बजे

21. हमारी सरकार सतत विकास के लिए ऊर्जा संरक्षण में विश्वास रखती है। इसी के मद्देनजर वितरण कम्पनियां ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही हैं। अब तक हरियाणा के 650 गांवों में काम्पैक्ट फ्लोरोसैंट लैम्प्स (Compact Fluorescent Lamps) लगाए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में भी काम्पैक्ट फ्लोरोसैंट लैम्प्स (Compact Fluorescent Lamps) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा के लोग इनके लाभ को समझने लगे हैं। इससे लोगों को वित्तीय लाभ हुआ है और प्रदेश में ऊर्जा की बचत हुई है।

22. बिजली वितरण में सुधार के लिए कृषि फीडरों को अलग करने, उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली शुरू करने, कण्डक्टर क्षमता को बढ़ाने, उपभोक्ता मीटरों को दूसरी

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

जगह लगाने जैसे अनेक कार्य प्रगति पर हैं। 11वीं योजना में सम्प्रेषण प्रणाली के उन्नयन पर 7698 करोड़ रुपए तथा वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने पर 6577 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गत तीन वर्षों में 68 नए सब-स्टेशन स्थापित किए गए 182 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई 37,386 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए और 1138 किलोमीटर लंबी नई सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गईं।

23. वर्ष 2008-09 में, बिजली क्षेत्र के लिए अक्षय ऊर्जा समेत योजनागत तथा योजनेतर 3528.88 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जबकि 2007-08 में यह 3149.88 करोड़ रुपए थी।

सिंचाई

24. प्रदेश भर में पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना हमारा चुनावी वादा था और हमने उस वादे को पूरा किया है। इस वादे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भाखड़ा मेन लाईन को हांसी-बुटाना ब्रांच से जोड़ने के लिए 109 किलोमीटर लंबी बहु-उद्देशीय सम्पर्क नहर का निर्माण शुरू किया, जिसके चालू वित्त वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है। इस नहर के पूरा होने के बाद मेवात के पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक नहर का निर्माण प्रस्तावित है। जवाहर लाल नेहरू फीडर की क्षमता 1500-1600 क्यूसिक से बढ़ाकर 2200 क्यूसिक की गई है तथा इस क्षमता को 2500 क्यूसिक तक और बढ़ाया जा रहा है।

25. यमुना नदी में उपलब्ध फालतू पानी का सदुपयोग करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पश्चिम यमुना नहर की मेन लाईन लोअर की क्षमता 13,500 क्यूसिक से बढ़ाकर 20,000 क्यूसिक की जा रही है और इस कार्य के जून, 2008 तक पूरा होने की सम्भवना है। मानसून के दौरान यमुना नदी के फालतू पानी का भूजल संभरण के लिए उपयोग करने हेतु दादूपुर-शाहबाद-नलवी सिंचाई नहर का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है। योजना का प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में पूरा होना सम्भावित है। यमुना नदी के फालतू पानी से अम्बाला और नारायणगढ़ के क्षेत्र को संभरण एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक अन्य योजना तैयार की गई है, जिसके आगामी वित्त वर्ष के दौरान शुरू होने की सम्भावना है।

26. औद्योगिक शहर गुड़गांव, मानेसर, बहादुरगढ़ एवं खरखौदा की भावी मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जलापूर्ति चैनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके वर्ष 2008-09 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है। कृषि भूमि एवं ग्रामीण आबादी को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वर्ष 2008-09 में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

27. वर्ष 2008-09 के दौरान, बाढ़ नियंत्रण तथा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण समेत सिंचाई के लिए योजनागत तथा योजनेतर 1477.21 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है, जबकि 2007-08 में 1373.66 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

28. हालांकि 31 मार्च, 1992 तक प्रदेश के सभी गांवों में पेयजल सुविधा पहुंचाई जा चुकी थी, तथापि कई गांवों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है। हमने वर्ष 2006-07 में पेयजल की कमी वाले 1103 गांवों की जलापूर्ति में वृद्धि की है तथा वर्ष 2007-08 में 500 और गांवों में वृद्धि होने की सम्भावना है। शेष गांवों में वर्ष 2008-09 में जल संवृद्धि का कार्य किया जाएगा।

29. इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को निःशुल्क व्यक्तिगत पेयजल कनैक्शन दिए जा रहे हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के तहत 3.30 लाख परिवारों को कनैक्शन देने की सम्भावना है तथा शेष परिवारों को वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कनैक्शन दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति के परिवारों को पानी के मासिक शुल्क की अदायगी में 50 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। सामान्य वर्ग के परिवारों को पानी के निजी कनैक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांवों में 500 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए की कनैक्शन फीस समाप्त कर दी गई है।

30. मेवात क्षेत्र में सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वित्तीय सहायता से 205.91 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी राजीव गांधी संवर्धन पेयजल परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में तीन रैनी वैल्ज़ का निर्माण किया जाएगा तथा उपयुक्त स्थानों पर स्थापित बूस्टिंग केन्द्रों वाले वितरण तंत्र के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, जून 2008 तक 290 नलकूप लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे 503 मेवात के गांव लाभान्वित होंगे।

31. प्रदेश के सभी शहरों में पाईप्स के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति एवं सीवरेज आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एन०सी०आर० के शहरों तथा 'काऊंटर मैगनेट' शहर हिसार के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

32. वर्ष 2008-09 में, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए योजनागत तथा योजनेतर 1237.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 2007-08 में इस क्षेत्र के लिए 1120.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

सड़कें एवं पुल

33. हमारी सरकार सड़कों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के निवेश का राजीव गांधी पुल एवं सड़क आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जो तीन चरणों में पूरा होगा। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत 1000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के लिए राज्य के संसाधनों के अलावा भारत सरकार तथा अन्य वित्तीय एजेंसियों से धन जुटाया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान 3200 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारा गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान 4500 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारा जाना प्रस्तावित है।

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

34. सड़क उपरिगामी पुलों (ROBs) के निर्माण की एक मास्टर योजना के तहत सरकार पहले ही 37 सड़क उपरिगामी पुल स्वीकृत कर चुकी है, जिनमें से तीन सड़क उपरिगामी पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 18 निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 10 सड़क उपरिगामी पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है। हमने वर्ष 2007-08 में 150 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया और वर्ष 2008-09 में 175 किलोमीटर लंबी नई सड़कों के निर्माण की योजना है।

35. हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से 450 करोड़ रुपए की लागत से 1085 किलोमीटर लंबी 108 ग्रामीण सड़कों को चौड़ा एवं सुदृढ़ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। वर्ष 2007-08 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 151.51 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 880 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुधार पर 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

36. वर्ष 2008-09 में सड़क, परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए योजनागत तथा योजनेतर 1921.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 2007-08 में इस क्षेत्र के लिए 1583.23 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां

37. खराब मौसम तथा कम वर्षा के बावजूद सरकार द्वारा आदानों की आपूर्ति, ऋण सहायता, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि पम्पों के लिए बिजली की आपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई गई सहायता से और हमारे किसानों की कड़ी मेहनत से प्रदेश में वर्ष 2007 में खरीफ खाद्यान्नों का 49.26 लाख क्विंटल का अब तक का रिकार्ड उत्पादन हुआ, जो गत वर्ष के 44.96 लाख क्विंटल उत्पादन की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, रबी 2007-08 के लिए निर्धारित किए गए 24 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए 24.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं की बुआई की गई है।

38. वर्ष 2008-09 में कृषि के ऐसे शाश्वत विकास की ओर हमारा ध्यान केन्द्रित होगा, जो भूमि की उर्वरा शक्ति की क्षतिपूर्ति करे, पर्यावरण व जल संसाधनों का संरक्षण करे और किसानों के लिये आर्थिक रूप से लाभदायक हो। हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा, जैविक खेती, मास मीडिया के माध्यम से विस्तार सेवाएं तथा मृदा, पानी एवं बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, समेकन एवं कम्प्यूट्रीकरण इस दिशा में शुरू की गई नीतिगत पहल का हिस्सा होंगे।

39. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' और 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' नामक दो नई योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को जीरो टिलेज मशीन, छिड़काव सैट, पोस्ट होल डिगर, स्ट्रा रीपर, रीपर बाइंडर, आलू लगाने तथा आलू की खुदाई करने जैसी कृषि मशीनों पर सबसिडी उपलब्ध करवाकर काश्त की नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे

समय की बचत होगी तथा उत्पादन लागत में कमी आएगी। अपने पसंदीदा निर्माताओं से ऐसे उपकरण खरीदने पर किसानों को सीधे 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की सबसिडी दी जाती है।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। प्रदेश में 94.45 लाख पशुओं की देखभाल के लिए 2605 पशु चिकित्सा संस्थाओं का एक तंत्र स्थापित है। पशुधन के जीवद्रव्य के सुधार, पहचान एवं संरक्षण के द्वारा मुर्राह विकास कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ किया जा रहा है। निदान सुविधाओं के साथ बेहतरीन पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सोनीपत, भिवानी एवं पंचकूला में आधुनिक सुविधाओं सहित पोलीक्लिनिक्स स्थापित किए जा रहे हैं। पांच जिलों, नामतः भिवानी, हिसार, झज्जर, जीन्द और रोहतक में एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है, जिससे 1.20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। दो हजार या इससे अधिक पशुओं वाली हर गौशाला में पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाने का एक अनूठा कदम उठाया गया है।

41. सरकार प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास पर समुचित बल दे रही है। लोगों, विशेषतः बेरोजगार ग्रामीण युवाओं तथा अनुसूचित जाति के किसानों को मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। भूमिगत खारे पानी व सेम वाले क्षेत्रों का समुचित उपयोग मछली / झींगा मछली उत्पादन हेतु उपलब्ध उचित प्रौद्योगिकियों के विविधिकरण पर बल दिया जायेगा। वर्ष 2008-09 के दौरान 3630 लाख मत्स्य बीज भण्डारण तथा 68,000 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

42. ग्रामीणों को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज की दरों को 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया है, जिससे प्रदेश के किसान लाभान्वित हुए हैं और ऋणों की समय पर अदायगी करने वालों को दो प्रतिशत की और छूट दी गई है। वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत लघु अवधि सहकारी ऋण ढांचे को अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 704 करोड़ रुपए प्राप्त होने की सम्भावना है। इस योजना के तहत अब तक केन्द्र सरकार से 240.34 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है।

43. वर्ष 2008-09 में कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन, वन, मछली पालन तथा सहकारिता समेत कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए योजनागत तथा योजनेतर 821.28 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

ग्रामीण विकास

44. ग्रामीण क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास करने तथा शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, 91 गांवों का चयन 'आदर्श गांव' के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। इसके लिए गत दो वर्षों के दौरान 175 करोड़ रुपए

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

की राशि उपलब्ध करवाई गई है। हाल ही में, आदर्श गांव योजना को पुनः संशोधित किया गया तथा सम्बन्धित विभागों को आदर्श गांवों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं जुटाकर इन्हें ग्रामीण विकास के केन्द्र बनाया जा सके।

45. राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति गांव उत्थान एवं मलिन बस्ती विकास योजना' नामक एक नई स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत वर्ष 2008-09 से अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या वाले सभी 391 गांवों में 50 लाख रुपए प्रति गांव खर्च करके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

46. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार ने इस वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर उत्कृष्ट स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को सफाई कर्मी नियुक्त करने के लिए 45.50 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। गांवों की जनसंख्या के आधार पर सभी गांवों में लगभग 11,000 सफाई कर्मी नियुक्त किए जा रहे है। यह योजना गांवों में स्वच्छता की स्थिति को सुधारने में लाभप्रद साबित होगी।

47. वर्ष 2006-07 में हरियाणा के दो जिलों में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' क्रियान्वित की गई तथा वर्ष 2007-08 में दो और जिलों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया। बहरहाल, वर्ष 2008-09 में प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वेच्छा से अकुशल कार्य के इच्छुक व्यक्तियों को गांवों में या गांव के निकट एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी पर रोज़गार उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना कोष से स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित की जा रही हैं।

48. वर्ष 2008-09 के लिए, विकास एवं पंचायत, ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास के लिए योजनागत तथा योजनेतर 634.87 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जबकि 2007-08 में यह आबंटन 409.45 करोड़ रुपए था।

शहरी विकास

49. हरियाणा, देश के उन राज्यों में से एक है, जहां तीव्रतम गति से शहरीकरण हो रहा है। इसलिए, हमारी सरकार प्रदेश में नियोजित शहरी विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। शहरी विकास के लिये बजट आबंटन में वर्ष 2005-06 से वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2007-08 के लिए योजनागत आबंटन 150 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 240 करोड़ रुपए किया जा रहा है। राज्य सरकार नगरपालिकाओं को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाकर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करती रहेगी ताकि शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार लाया जा सके।

50. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत फरीदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1203.59 करोड़ रुपए की सात विस्तृत परियोजना रिपोर्टस भारत सरकार को प्रस्तुत की गई हैं। इसमें से 275.33 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और 21.39 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। अब पंचकूला को भी चण्डीगढ़ और मोहाली के साथ ट्राई-सिटी के रूप में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किया गया है। सड़क, जल निकासी, जलापूर्ति एवं सीवरेज जैसी आधारभूत संरचनाओं की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा के 73 शहरों के लिए नगर विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। पंचकूला शहर के लिये एक विकास योजना तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

51. छोटे एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना के तहत रोहतक, करनाल, इन्द्री, यमुनानगर एवं जगाधरी की समेकित ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु चार विस्तृत परियोजनाओं तथा बहादुरगढ़ में 100.96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवरेज प्रणाली एवं सीवेज उपचार प्लांट की परियोजना स्वीकृति व धनराशि जारी करने हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है।

52. नगर एवं आयोजना विभाग समेत शहरी विकास क्षेत्र का योजनागत तथा योजनेतर कुल आबंटन वर्ष 2007-08 में 269.56 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2008-09 में 399.98 करोड़ रुपए किया गया है।

शिक्षा एवं खेल

53. शिक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा के लिए बजट आबंटन को वर्ष 2004-05 में 1450 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2007-08 में 2732.92 करोड़ रुपए किया गया। वर्ष 2008-09 में शिक्षा के लिए 3139.08 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

54. स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और वर्कबुक्स उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए वर्कबुक्स, परियोजना आधारित अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान का विषय शुरू किया जा रहा है। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिये भी नीतिगत निर्णय लिये जा रहे हैं।

55. वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा को चरणबद्ध ढंग से अनिवार्य बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में 200 बड़े वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए पूर्णतः सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तथा योग्य शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। योजनागत संसाधनों की मदद से तथा भारत सरकार की योजनाओं के तहत प्रदेश के स्कूल तंत्र का उन्नयन किया जाएगा।

56. प्रदेश में उच्चतर शिक्षा को भी पूर्णतः नया रूप दिया जाना प्रस्तावित है। आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी एवं निजी कालेजों में बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी कॉम जैसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

कालेज के विद्यार्थियों के लिए भी कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। शुरू में, आगामी वित्त वर्ष से 25 बड़े कालेजों में इसे अनिवार्य किया जाएगा। विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य संबंधी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाकर विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है। कालेजों में सैमेस्टर प्रणाली शुरू किया जाना भी प्रस्तावित है।

57. चालू वित्त वर्ष के दौरान एजुसैट (Edusat) तंत्र का विस्तार किया गया और इसे आगे और सुदृढ़ किया जाएगा। पहले से ही विद्यालयों में शुरू की गई समैस्टर प्रणाली में भी सुधार लाये गये हैं।

58. वर्ष 2006 में दोहा (कतर) में आयोजित 15वें एशियाई खेलों में प्रदेश के 23 खिलाड़ियों ने पदक जीते। इन खिलाड़ियों को 148 लाख रुपए के नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 28 नवम्बर, 2007 से 2 दिसम्बर, 2007 तक कोलकाता में आयोजित 12वीं एशियाई महिला रोल्लर स्कैटिंग हॉकी टूर्नामैंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस टीम में प्रदेश के आठ खिलाड़ी थे, जिन्हें एक-एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

59. मोती लाल नेहरू खेल विद्यालय, राई में 3.45 करोड़ रुपए की लागत से एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सैन्थेटिक हॉकी ग्रास सरफेस (Synthetic Hockey Grass Surface) (Astroturf) बिछाया जा रहा है। खिलाड़ियों के खुराक भत्ते में पर्याप्त वृद्धि करने का भी हमारा इरादा है। हम ग्रामीण विद्यार्थियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक गांवों में ग्रामीण खेल स्टेडियमों का भी निर्माण करवा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं

60. प्रदेश में 50 अस्पतालों, 85 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 420 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2433 उपकेन्द्रों, 20 जिला टी०बी० सैंटरों, 41 औषधालयों, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रोहतक और चिकित्सा महाविद्यालय, अग्रोहा (हिसार) और मुलाना (अम्बाला) के नेटवर्क से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

61. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति गृहों के माध्यम से संस्थागत प्रसूति की सेवाएं उपलब्ध होने से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, जोकि एक उत्साहवर्धक परिणाम है। सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 475 प्रसूति गृह स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान ऐसे 500 और प्रसूति गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है।

62. जिला मेवात में गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में ले जाने के लिए 2 अक्तूबर से 9 एम्बुलैंस उपलब्ध करवाकर मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं आरम्भ की गई हैं। एम्बुलैंस के चालकों को मोबाइल फोन दिये गये हैं ताकि समय पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राज्य के मोरनी (पंचकूला) जैसे अन्य दुर्गम क्षेत्रों में इसी प्रकार की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

63. राज्य सरकार द्वारा लोगों को उच्चकोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये निजी क्षेत्र के विशाल संसाधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र द्वारा गुड़गांव के सामान्य अस्पताल में न्यूरोलॉजी तथा मनोरोग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 9 औषधालयों में से एक औषधालय का प्रबन्ध कार्य सीग्राम इंडिया नामक कम्पनी ने अपने हाथ में लिया है, जो इसका संचालन सफलतापूर्वक कर रही है। शेष आठ औषधालयों को भी गैर-सरकारी संगठनों या निजी एजेंसियों को सौंपने का प्रस्ताव है, जिसके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से भी आवेदन प्राप्त हुए हैं।

64. राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण का कार्य पुलिस थानों की बजाय स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सौंपा है, जिसके परिणामस्वरूप जन्म पंजीकरण वर्ष 2005 के 78.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006 में 92.4 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार मृत्यु पंजीकरण वर्ष 2006 के दौरान बढ़कर 81.5 प्रतिशत हो गया। लिंग अनुपात के परिवीक्षण के लिए भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे आकलनों के आधार पर प्रदेश में लिंग अनुपात, जो वर्ष 2005 में सिर्फ 823 दर्ज किया गया था, नवम्बर, 2007 में बढ़कर 860 हो गया है।

65. आयूष और चिकित्सा शिक्षा समेत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण क्षेत्र का योजनागत व योजनेतर आबंटन वर्ष 2007-08 में 581.60 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2008-09 में 684.04 करोड़ रुपए किया गया है।

कमजोर वर्ग का कल्याण

66. हरियाणा सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों, किन्नरों, बोनों, अल्पसंख्यकों और ऐसे परिवारों, जिनमें केवल लड़कियां हैं, को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं।

67. हरियाणा सरकार ने अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु या स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में हरियाणा के 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के सभी पात्र व्यक्तियों को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

68. राज्य सरकार का स्कूलों में न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 2008-09 से एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। पहले यह कहते थे कि 18 वर्ष से कम को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मगर इस स्कीम के तहत 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

69. हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी शहरी सम्पदाओं में वृद्धों के लिए 'डे-केयर सैंटर्ज' (Day Care Centres) स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इन केन्द्रों

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

में वरिष्ठ नागरिकों को इन्डोर खेलों, जल-पान, पुस्तकालय, वाचनालयों, चिकित्सा इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

70. अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने हेतु उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष से ही छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग इत्यादि की शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए केन्द्र की हिस्सेदारी से पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की एक योजना क्रियान्वित करने का भी निर्णय लिया है।

71. अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए वर्ष 2005-06 से 'डॉ. अम्बेदकर मेधावी छात्र योजना' शुरू की गई थी। बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भी वर्ष 2007-08 से इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जातियों के और अधिक विद्यार्थियों को इस स्कीम में शामिल करने का भी हमारा प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि में दस गुणा वृद्धि करते हुए 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है।

महिला एवं बाल विकास

72. हम महिलाओं और बच्चों के विकास और उनके स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। घटता लिंगानुपात एक बड़ी चिंता का विषय है। वर्ष 2005-06 में शुरू की गई लाडली योजना हमारी सरकार द्वारा इस संदर्भ में उठाये गये महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक है, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे है। बच्चों, विशेषकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में रक्त की कमी और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2008-09 से एक विशेष स्कीम शुरू की जा रही है। इस स्कीम के तहत उनके आहार में पोषक तत्वों, फोलिक एसिड तथा विटामिन 'ए' की वृद्धि की जाएगी और उन्हें कृमि नाशक दवाई पिलाई जाएगी। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों की बस्तियों में अथवा उनके निकट आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

73. वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये अन्य प्रमुख कदमों में महिलाओं एवं बच्चों से सम्बनिधत मामलों पर उचित कार्यवाही करने के लिए ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम स्तरीय समितियों का गठन करना शामिल है। लगभग 6,500 ग्राम स्तरीय समितियों ने कार्य आरम्भ कर दिया है और इन समितियों ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के लाभपात्रों के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया है। इस व्यवस्था ने लगभग एक लाख महिलाओं को निर्णय लेने की अहम् भूमिका में शामिल कर दिया है।

शिक्षित महिलाओं के 6000 से अधिक साक्षर महिला समूह, जो सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, गठित किये गये हैं, जो गांवों में सामाजिक बदलाव लाने और विकास करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की तरह कार्य करेंगे।

74. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास तथा पोषाहार समेत समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए वर्ष 2008-09 में योजनागत तथा योजनेतर 1264.24 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जबकि 2007-08 में यह 1125.56 करोड़ रुपए थी।

औद्योगिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा

75. प्रदेश में तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण तकनीकी मानवशक्ति की मांग तेजी से बढ़ रही है। रोज़गार के नये अवसरों का लाभ उठाने के लिये हमारी सरकार तकनीकी शिक्षा के विस्तार और औद्योगिक प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दे रही है। इस समय, प्रदेश में 31 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित 195 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में 31 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है, जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान छः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किये जाने और सात एस०सी० विंग (S.C. Wing) शुरू किये जाने का विचार है।

76. इस समय, हरियाणा राज्य में दो तकनीकी विश्वविद्यालय, 61 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 90 एम०सी०ए०/एम०बी०ए० महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय विभाग, 27 फार्मेसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग, तीन होटल प्रबन्धन महाविद्यालय तथा 76 बहुतकनीकी संस्थान हैं। छोटू राम राज्य इंजीनियरिंग कालेज, मुरथल का दर्ज़ा बढ़ाकर इसे दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना दिया गया है।

77. वर्ष 2008-09 के दौरान सांपला और मोरनी में दो नये बहुतकनीकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पबनावा (कैथल), उमरी (कुरुक्षेत्र) और दामलावास (रेवाड़ी) में सार्वजनिक निजी भागीदारी से नये संस्थान खोलने का विचार है। रोहतक में फैशन एण्ड डिज़ाईन (Fashion and Design), ललित कला (Fine Arts), फिल्म एण्ड टी०वी० प्रोफैशनल स्टडीज़ (Film and TV Professional Studies) के नये संस्थान आरम्भ किए जा रहे हैं। राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में फैशन डिज़ाईन (Fashion Design), आन्तरिक साज-सज्जा (Interior Design), लेखा एवं लेखा परीक्षा (Accounts and Audit) तथा टूर्ज़ एण्ड ट्रैवल्ज़ मैनेजमैंट (Tours and Travels Management) जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

78. तकनीकी शिक्षा विभाग ने कागज रहित दाखिलों के लिए भारत सरकार से "ई शासन-2007-08 के लिए गोल्डन आइकन अवार्ड" प्राप्त किया है।

79. औद्योगिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के लिए योजनागत तथा योजनेतर आबंटन वर्ष 2007-08 में कुल 291.22 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2008-09 में 351.32 करोड़ रुपए किया गया है।

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

उद्योग

80. वर्ष 2005 में हमारी सरकार के सत्ता सम्भालने के बाद प्रदेश में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश हुआ है और 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की परियोजनाएं विचाराधीन हैं। अब तक प्रदेश में 10,500 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है, जिसमें से 7000 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नई औद्योगिक नीति-2005 लागू होने के बाद आया है।

81. राज्य को विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 92 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें दो लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश होगा और 20 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा 51 प्रस्तावों को सैद्धान्तिक/औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस वर्ष दिसम्बर, 2007 तक 33,762 करोड़ रुपए के निवेश के 27 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें चार लाख लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है।

82. राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत संरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने की नीति को जारी रखेगी। राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास और रोज़गार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए हमारी नीतियां ऐसी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर केन्द्रित रहेंगी, जो दूसरे कई उद्योगों के विकास में सहायक होंगी। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र, वैज्ञानिक उपकरणों, आटोमोबाईल्ज़ एवं आटो कम्पोनैंटस इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

83. वर्ष 2008-09 में, उद्योग विभाग के लिए योजनागत तथा योजनेतर कुल 231.52 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2007-08 में 89.99 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

श्रम एवं रोज़गार

84. उद्योगों की सुविधा के लिए कारखाना अधिनियम-1948 और अनुबंध श्रमिक (आर एण्ड ए) अधिनियम-1970 के अन्तर्गत पंजीकरण और लाईसैंस प्रदान करने की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदान की गई हैं। अनुबंध श्रम अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रम उपायुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में पंजीकरण एवं लाईसैंस अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

85. श्रमिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रदेश में नौ औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम अदालतें कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, काफी समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए लोक अदालतों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन पहली जुलाई, 2007 से संशोधित करके 3510 रुपये प्रति मास किया गया है और श्रमिक श्रेणी से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि को बेअसर करने के लिए हर छः महीने में इसे अपडेट किया जाएगा।

86. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पहली अप्रैल, 2008 से चार जिलों के लिए स्वीकृत की गई है, के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों का 30,000 रुपए तक का बीमा किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत चार और जिलों को शामिल किये जाने की सम्भावना है। प्रीमियम राशि का खर्च केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में वहन करेंगी। बीमाकृत परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे और यह लेन-देन नकदी रहित और कागज़ रहित होगा।

87. वर्ष 2008-09 के दौरान श्रम एवं रोज़गार विभाग के लिए योजनागत तथा योजनेतर 33.41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट अनुमान 2008-09

88. अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

89. जैसा कि मैंने अपने अभिभाषण के आरम्भ में कहा है कि वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना के लिए 6650 करोड़ रुपए का आबंटन प्रस्तावित है। बिजली क्षेत्र को 867 करोड़ रुपए, सिंचाई क्षेत्र को 790 करोड़ रुपए, जलापूर्ति एवं स्वच्छता को 653 करोड़ रुपए तथा सड़क एवं परिवहन क्षेत्र को 766 करोड़ रुपए मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्र के अन्य कार्यक्रमों के लिए आबंटन 2476 करोड़ रुपए होगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा के लिए 970 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए 640 करोड़ रुपए, पोषाहार समेत महिला एवं बाल विकास के लिए 172 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 164 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 130 करोड़ रुपए शामिल हैं।

90. वर्ष 2007-08 भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों के अनुसार 12.58 करोड़ रुपए के अधिशेष के साथ शुरू हुआ और 3.80 करोड़ रुपए के अधिशेष के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। वर्ष का लेन-देन 8.78 करोड़ रुपए की कमी दर्शाता है।

91. वित्त वर्ष 2008-09 की 3.80 करोड़ रुपए के अधिशेष के साथ आरम्भ होने और 7.01 करोड़ रुपए के अधिशेष के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान होने वाला लेन-देन 3.21 करोड़ रुपए का अधिशेष दर्शाता है।

92. बजट अनुमानों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास योजनाओं के लिए 932.84 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रावधान के अतिरिक्त राज्य योजना के लिए 6650.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है।

93. राजस्व खातों में, वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों में प्राप्तियां 17917.35 करोड़ रुपए थी, जिनकी वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमानों में बढ़कर 19,629.69 करोड़ रुपए होने की संभावना है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां 21695.32 करोड़ रुपए होने की संभावना है, जो 2007-08 के बजट अनुमानों से 3777.97 करोड़ रुपए अधिक हैं।

[श्री बिरेन्द्र सिंह]

94. वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों में राजस्व खर्च 16768.55 करोड़ रुपए दर्शाया है, जिसकी वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमानों में बढ़कर 18135.00 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में 20280.84 करोड़ रुपए का राजस्व खर्च दर्शाया गया है, जो वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों से 3512.29 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान 1414.48 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्शाते हैं।

95. पूंजीगत खातों में, 2007-08 का बजट खर्च 2983.31 करोड़ रुपए है, जिसकी वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमानों में बढ़कर 3385.64 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में पूंजीगत खर्च 3750.99 करोड़ रुपए है।

96. वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में राज्य के समेकित कोष में कुल प्राप्तियां 25,987.40 करोड़ रुपए की दिखाई गई हैं, जबकि वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों में ये 21,930.89 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमानों में ये 20,610.11 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में 26,420.98 करोड़ रुपये का खर्च दर्शाया गया है, जबकि वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों में यह 21,967.95 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमानों में 22,262.45 करोड़ रुपए है।

97. आशा है कि करों के बढ़िया अनुपालन और अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों के हिस्से व अन्य अन्तरणों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार, राज्य के कर राजस्व में भी काफी वृद्धि होने का अनुमान है। मुझे विश्वास है कि हम इस सदन के माननीय सदस्यों और प्रदेश के लोगों के सहयोग और सहायता से प्रस्तावित योजनागत परिव्यय का पूरा उपयोग करके अपने सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सफल होंगे।

98. महोदय, अब मैं वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द!

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, on Wednesday the 19th March, 2008.

*11.52 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 19th March, 2008.

44393—H.V.S.—H.G.P., Chd.